https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

'भारत की सामूहिक शक्ति की सफलता का उत्तम उदाहरण है जीएसटी'

वर्ष-12, अंक-16, 16-31 अगस्त, 2017 (पाक्षिक) ₹20

बनाएं भाजपा को 'अपराजेय'

कम्युनिस्टों की तालिबानी मानसिकता

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चले हैं भारत के कदम

भारत का बदलता परिवहन परिदृश्य

उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के प्रवास की छवियां

उत्तर प्रदेश

हरियाणा

हरियाणा

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

हरियाणा

उत्तर प्रदेश

हरियाणा

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com

वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **योगीजी के नेतृत्व में राज्य में विकास की नई कहानी लिखेंगे: अमित शाह**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान 30 जुलाई को अटल कन्वेंशन सेंटर, लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की...

वैचारिकी

सदोष शिक्षा पद्धति बेकारी के लिए जिम्मेदार 17

श्रद्धांजलि

श्री अरबिंदो: शत-शत नमन! 19

लेख

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चले हैं भारत के कदम 20

भारत का बदलता परिवहन परिदृश्य 22

शीर्ष पर भाजपा 24

कम्युनिस्टों की तालिबानी मानसिकता 25

अन्य

यह समय परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों और प्राइवेट इक्विटी संस्थानों के लिए बेजोड़ अवसर है : अरुण जेटली 16

वेंकैया नायडू बने 13वें उप राष्ट्रपति 26

राज्यसभा में बिल अटका कर कांग्रेस ने देश के पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया है: अमित शाह 27

रा.स्व.संघ स्वयंसेवक राजेश की हत्या 28

प्रधानमंत्री का पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को मार्मिक पत्र 30

भारत की सामूहिक शक्ति की सफलता का उत्तम उदाहरण है जीएसटी 31

पत्र-पत्रिकाओं से... 33

संगठनात्मक गतिविधियां

10 **'खट्टर सरकार ने राजनीति की संस्कृति बदली'**

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 2 अगस्त को डॉ...

13 **पश्चिम बंगाल प्रदेश के भाजपा मुखपत्र 'कमल वार्ता' का लोकार्पण**

पश्चिम बंगाल भाजपा पत्रिका और प्रकाशन विभाग ने 30 जुलाई 2017 को संपन्न...

सरकार की उपलब्धियां

14 **बाढ़ प्रभावित उत्तर-पूर्वी राज्यों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक सहायता राशि की घोषणा**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अगस्त को बाढ़...

15 **रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की**

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 अगस्त को नई रेपो रेट दर की घोषणा करते हुए रेपो रेट में 0.25 बेसिस...

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

उस समय का नारा था - 'करेंगे या मरेंगे' लेकिन आज का मंत्र होना चाहिए - 'करेंगे और कर के रहेंगे।'

@JPNadda

असम, मणिपुर और गुजरात में आयी बाढ़ से ग्रसित जनता की मदद हेतु रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्त्वावधान से सहायता सामग्री को रवाना किया।

@PrakashJavdekar

हम ऐसी उपाधि देना चाहते हैं, जिसमें ज्ञान के साथ कौशल का भी समावेश हो।

@byadavbjp

राज्यसभा में कांग्रेस द्वारा जानबूझकर ऐसा संशोधन लाया गया जो संविधान सम्मत नहीं था। ओबीसी विधेयक को पारित न होने देकर उन्होंने फिर धोखा दिया है।

facebook

हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति में नहीं आये, भाजपा की स्थापना मां भारती को पुनः विश्वगुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिए हुई थी। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है और अंत्योदय हमारा लक्ष्य। अंत्योदय का अर्थ विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति के बराबर लाना।

— अमित शाह

अन्नदाता किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए कृषि कनेक्शन नीति-2017 के प्रावधानों का अनुमोदन किया गया है। हमने गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लघु सीमान्त किसानों तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना के समीप रहने वाले किसानों को 5 एच.पी. तक के कृषि कनेक्शन के लिए डिमांड नोट जारी करने में तीन साल तक की ओवरराइडिंग प्राथमिकता देने का प्रावधान किया है। इससे हमारे किसानों को फायदा मिलेगा और साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी। **—वसुंधरा राजे**

उत्तराखंड के भूगोल के कारण यहां हजारों लीटर बारिश का पानी बहकर बेकार चला जाता है। सरकार वर्षा-जल के संरक्षण के प्रति गंभीर है, ताकि पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटा जा सके। हमारी कोशिश है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी राज्य के काम आ सके।

— त्रिवेन्द्र सिंह रावत

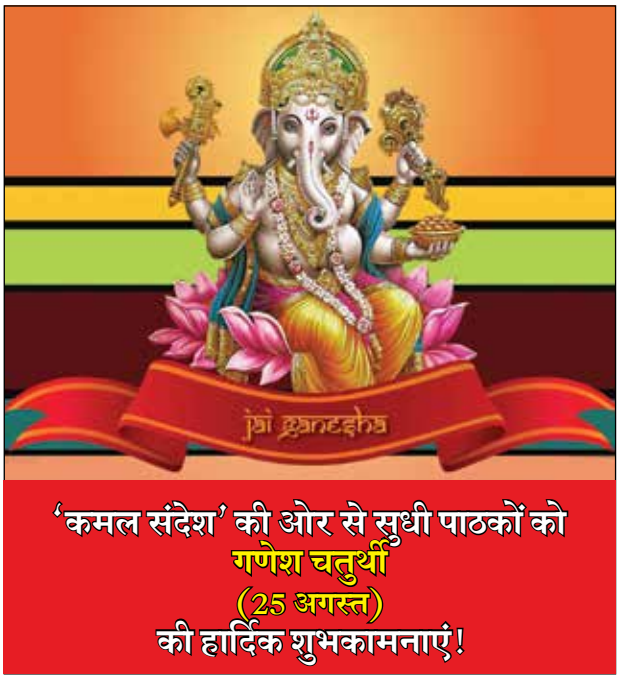

केरल में कम्युनिस्ट हिंसा का तांडव

पूरा देश भली–भांति जानता है कि कम्युनिस्टों का राजनैतिक हिंसा में अटूट विश्वास रहा है। जहां भी इन्हें सत्ता प्राप्त हुई, इन्होंने अपने राजनैतिक विरोधियों का सफाया करने तथा सभी लोकतांत्रिक आवाज को दबाने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी। पूरे विश्व में इनके द्वारा किये गये जनसंहारों में जहां लाखों निरपराध मारे गये, वहीं इससे भी कई गुणा अधिक लोग उजाड़ दिये गये। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ–भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रही हिंसा भी कोई अपवाद नहीं है। तिरुवंतपुरम में 34 वर्षीय युवा राजेश की जघन्य हत्या से प्रमाणित होता है कि कम्युनिस्ट जब सत्ता में आते हैं, तब सरकारी मशीनरी के सहारे वे और भी अधिक हिंसक हो जाते हैं। जिस बर्बर तरीके से इस कायरतापूर्ण हत्या को अंजाम दिया गया, उससे कम्युनिस्टों की हिंसक विचारधारा का पता तो चलता ही है, साथ ही इनका भयानक चेहरा उजागर होता है। जिस क्रूरता के साथ राजेश की हत्या हुई है उसकी देश के सभी लोकतांत्रिक आवाजों को मिलकर भर्त्सना कर कम्युनिस्ट हिंसा को बेनकाब करना चाहिए।

राजेश की हत्या कम्युनिस्टों द्वारा जनता को भयाक्रांत करने के व्यापक षड्यंत्र का एक हिस्सा है। जिस निर्दयतापूर्वक यह लोमहर्षक कृत्य किया गया है, उससे स्पष्ट है कि कम्युनिस्ट जन–जन के मन में डर बिठाकर उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं। इसी प्रकार से 12 मई 2017 को बीजू तथा 18 जनवरी 2017 को संतोष की हत्या हुई, जिससे इनके खतरनाक इरादों का पता चलता है। जैसे ही कम्युनिस्टों को केरल में सत्ता प्राप्त हुई, संघ–भाजपा के विरुद्ध इनके हमले तेज हो गये। 2016 में सुजीथ, सीके रामचंद्रन, बीनीश एवं रामीथ की हत्या राजनैतिक विरोध को नेस्तनाबूद करने के कम्युनिस्टों की मानसिकता का ही एक हिस्सा है। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि मुख्यमंत्री तक के क्षेत्र में हत्या की जा रही है। कम्युनिस्टों को सुनियोजित तरीके से राजनैतिक विरोधियों की हत्या करने की घटनाओं को इनके नेता ही अपने भाषणों में कई बार स्वीकार कर चुके हैं। भाकपा के पूर्व सांसद एपी अब्दुल्लाकुट्टी ने बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 2008 में अपनी पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि किस प्रकार से राजनैतिक विरोधियों का सफाया करना चाहिए, यह बंगाल से सीखना चाहिये। उन्होंने कहा था, ''वे इसे बिना एक भी बूंद खून बहाये करते हैं। उन्हें (विरोधियों को) अगवा कर गहरे गड्ढे में एक बोरी नमक के साथ दफना दिया जाता है। दुनिया को ना तो खून का, ना फोटो (हत्या) का, ना कोई खबर मिल पाती है।'' अब्दुल्लाकुट्टी के अनुसार उस बैठक में सांसद पी. करूणाकरण एवं पी. साथीदेवी तथा कन्नूर के विधायक उपस्थित थे। इसमें अब कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि जब स्वयं पिनराई मुख्यमंत्री हैं तब विरोधियों की हत्याएं होंगी ही। इससे यह वास्तविकता भी सामने आती है कि भारत जैसे लोकतंत्र में भी कम्युनिस्ट हिंसक राजनीति पर आमादा हैं।

अब जबकि कम्युनिस्ट देश में एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, वे कितना भी हिंसा करें अब उनका पतन तय है। लोकतंत्र में हिंसा के लिये कोई जगह नहीं, पर कम्युनिस्ट इस सच्चाई को समझ नहीं पाये। कम्युनिस्ट हिंसा में हुए बलिदानियों का खून व्यर्थ नहीं जायेगा, अपने कुकृत्यों का हिसाब उन्हें जनता को देना ही पड़ेगा।

केरल की हिंसक घटनाओं तथा निरंतर हो रही जघन्य हत्याओं से पूरा देश विचलित है। ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में अपनी दुर्दशा से कम्युनिस्ट कोई सबक नहीं ले पाये हैं। भारत में भी उन्हें पश्चिम बंगाल में हुई अपनी पराजय से सबक लेना चाहिये, जब प्रदेश की जनता ने उन्हें उनकी करनी की सजा दी।

त्रिपुरा में भी इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आने वाले चुनावों में ये हार का मुंह देखने वाले हैं। परन्तु सबसे दुर्भाग्यजनक है इन घटनाओं पर मीडिया के एक वर्ग, मानवाधिकार की दुहाई देने वाले तथा सिविल सोसाईटी का दावा रखने वाले इस विशेष वर्ग की चुप्पी। इतने वीभत्स हत्याकांड पर भी इस प्रकार की चुप्पी इस वर्ग की राजनैतिक कुंठा को उजागर करती है। अब जबकि कम्युनिस्ट देश में एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, वे कितनी भी हिंसा करें अब उनका पतन तय है। लोकतंत्र में हिंसा के लिये कोई जगह नहीं, पर कम्युनिस्ट इस सच्चाई को समझ नहीं पाये। कम्युनिस्ट हिंसा में हुए बलिदानियों का खून व्यर्थ नहीं जायेगा, अपने कुकृत्यों का हिसाब उन्हें जनता को देना ही पड़ेगा। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

योगीजी के नेतृत्व में राज्य में विकास की नई कहानी लिखेंगे: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान 30 जुलाई को अटल कन्वेंशन सेंटर, लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और कार्यपद्धति पर विस्तार से चर्चा की। विदित हो कि श्री शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में थे।

श्री शाह ने कहा कि आज देश में लगभग 1650 छोटी-बड़ी पार्टियों में से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है तो देश का लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाता है, लेकिन यदि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो देश का लोकतंत्र भी मजबूत बना रहता है और देश विकास के पथ पर भी गतिशील बना रहता है। उन्होंने कहा कि देश की अधिकतर पार्टियों में सबको पता है कि उसका अगला अध्यक्ष कौन होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, यह सब लोगों को पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, यह किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष वंश, जाति अथवा धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर तय होते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेता अपने कृतित्व, परिश्रम, मेधा, परफॉरमेंस और अपने निर्मल चरित्र के आधार पर बनते हैं। यही कारण है कि यहां एक बूथ कार्यकर्ता भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है और एक गरीब का बेटा व पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा देश का लोकतंत्र बचा कर नहीं रखती तो आज एक गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता और यह भी सच है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का आतंरिक लोकतंत्र मजबूत है, इस देश के लोकतंत्र पर कोई आंच नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी का चयन करते वक्त यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि उस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है या नहीं। यदि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो उस पार्टी में जातिवाद और परिवारवाद हावी हो जाता है और योग्यता को आगे बढ़ने का मौक़ा नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि देश में कई सारी पार्टियां हैं जो परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर ही चल रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं देश की जनता का भी आह्वान करना चाहूंगा कि वे भी ऐसे दलों को चुनें, जहां आंतरिक लोकतंत्र हो।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 1950 से 2017 की जन संघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा का मूल सिद्धांत अंत्योदय, एकात्म मानववाद और

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय से हमारा मतलब है - विकास की दौड़ में पीछे छूट गए समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास की दौड़ में खड़े सबसे पहले व्यक्ति के बराबर लाना और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने अंत्योदय के लक्ष्य को सामने रखते हुए एक सर्वस्पर्शी एवं सर्व-समावेशी विकास का मॉडल अपनाया है, जो हर वर्ग को स्पर्श करता हो और सबको समाहित करता हो। उन्होंने कहा कि 50 सालों से हम इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि 10 सदस्यों से जन संघ के रूप में शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज उस पार्टी के देश में 1387 विधायक हैं, देश के 18 राज्यों में भाजपा एवं सहयोगियों की सरकारें हैं। 330 सांसद हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि किसी पार्टी का सिद्धांत कैसा है, यह पार्टी के कार्यक्रमों से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि जन संघ की स्थापना से लेकर आज तक हमने जितने भी आंदोलन हाथ में लिए, वे सभी देश और समाज की भलाई के लिए थे। चाहे वह गौ-हत्या पर प्रतिबंध का आंदोलन हो, कच्छ बचाने का आंदोलन हो, गोवा का सत्याग्रह हो, राम जन्म भूमि का आंदोलन हो, कश्मीर को बचाने का आंदोलन हो या फिर भ्रष्टाचार उन्मूलन का अभियान हो।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के क्या सिद्धांत हैं, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थापना सिद्धांत के लिए हुई ही नहीं थी, आजादी प्राप्त करने के लिए हुई थी और इसमें सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सिद्धांतों के आधार पर कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भारतीय जन संघ की विचारधारा में एक बड़ा मूल अंतर यह था कि कांग्रेस देश का नवनिर्माण करना चाहती थी, जबकि भारतीय जन संघ देश की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली वैभव के आधार पर देश का पुनर्निर्माण करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं है, वह देश का विकास नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सिद्धांतों के आधार पर चलती है और देश के खोये हुए गौरव को पुनर्स्थापित करना चाहती है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार के तीन साल पूरे हुए हैं, लेकिन इन तीन सालों में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाए। इस प्रकार की पारदर्शी सरकार हमने देश को दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार पॉलिसी से ग्रस्त थी, अर्थव्यवस्था लगातार नीचे की ओर जा रही थी, देश की सुरक्षा खतरे में थी। उन्होंने कहा कि 2014-2017 के इस सफ़र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास की नई कहानी लिखी है। भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय देश की विकास दर 8 प्रतिशत से ऊपर थी, कांग्रेस की सोनिया-मनमोहन सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को 4.4% पर लाकर छोड़ा। हम फिर से इन तीन सालों में विकास दर को 7% से ऊपर लाने में सफल हुए हैं और यह लगातार आगे की ओर बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये प्रधानमंत्री जी ने देश को दुनिया के सामने एक मजबूत राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि तीन वर्षों में मोदी जी ने देश को कांग्रेस के समय की पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर निकालने का काम किया है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी ने हर मोर्चे पर सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के विकास व गरीब-कल्याण के लिए लगभग 106 योजनाओं की शुरुआत की है और इनमें से एक भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी एक वर्ग के लिए बनी हो। उन्होंने कहा कि 104 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर भारत अंतरिक्ष के अंदर दुनिया की एक प्रमुख ताकत के रूप में उभरा है, 40 सालों से लंबित 'वन रैंक, वन पेंशन' को मोदी सरकार ने एक ही साल में क्रियान्वित कर भूतपूर्व सैनिकों के खाते में इसका फायदा पहुंचाने का प्रबंध किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के लगभग 2.25 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस सिलिंडर पहुंचाया गया है, साढ़े चार करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है और 28.5 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोल कर उन्हें देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जो गरीबों की बात करते हैं, उन्होंने 70 सालों तक गरीब कल्याण के कार्यों की अनदेखी की, इसे पूरा नहीं किया, इसलिए हम इसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों की बात करने वाले 70 सालों में गरीबों के घर में न तो गैस पहुंचा पाए, न शौचालय पहुंचा पाए, न बिजली पहुंचा पाए, न पीने के पानी की व्यवस्था कर पाए और न ही बैंक अकाउंट खोल पाए। उन्होंने कहा कि आज यदि देश में गरीबों की जिंदगी में बदलाव आ पाया है, आज यदि दुनिया के सभी देश भारत में निवेश करना चाहते हैं तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व

में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को जाता है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की राजनीति से जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को ख़त्म करने का काम किया है, इसे उत्तर प्रदेश के चुनाव ने साबित करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार गरीबों, किसानों, दलितों, शोषितों, युवाओं एवं महिलाओं की सरकार है। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि योगीजी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में भी विकास की नई कहानी लिखेंगे और इसे देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनायेंगे।

प्रेस वार्ता (लखनऊ)

'विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने अपने तीन दिवसीय उत्तर प्रदेश प्रवास के तीसरे और अंतिम दिन 31 जुलाई को प्रदेश भाजपा कार्यालय, लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार एवं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। विदित हो कि श्री शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश में थे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय हर महीने घपले-घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते रहते थे। लगभग 12 लाख करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार देश की जनता के सामने आया, लेकिन आज देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐसी भ्रष्टाचार-मुक्त, पारदर्शी एवं निर्णायक सरकार काम कर रही है जिस पर तीन साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाए। सोनिया-मनमोहन की यूपीए सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त थी। उस यूपीए सरकार का हर मंत्री अपने-आप को प्रधानमंत्री समझता था और प्रधानमंत्री को तो कोई प्रधानमंत्री मानता ही नहीं था। उन्होंने कहा कि कई सरकारें 50 सालों में एक दो काम ऐसे करती हैं जो ऐतिहासिक होती है, लेकिन मोदी सरकार ने तीन साल में 50 ऐसे काम किये हैं जो ऐतिहासिक हैं।

श्री शाह ने कहा कि हमें विरासत में एक खस्ताहाल अर्थव्यवस्था मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केवल तीन सालों में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। उन्होंने कहा कि आज शेयर बाजार अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर है और हमने अर्थव्यवस्था के सभी मापदंडों पर अच्छी सफलता अर्जित की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार की रचना हुई थी, तब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये सरकार देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित और वंचितों की सरकार होगी और इन तीन वर्षों में मोदी सरकार ने इसे अक्षरशः सिद्ध करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से देश के पांच करोड़ गरीब माताओं के घरों में गैस सिलिंडर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 2.5 से अधिक गैस कनेक्शन के वितरण का काम पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि साढ़े चार करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण कर महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। 28.5 करोड़ से अधिक लोगों के बैंक अकाउंट खोल कर उन्हें देश के अर्थतंत्र की मुख्यधारा में जोड़ा गया है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवच भी प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से देश के 7.64 करोड़ लोगों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराये गए हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी के माध्यम से 'एक राष्ट्र, एक कर' का

स्वप्न साकार करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 70 साल बाद भी बिजली से वंचित 18 हजार से अधिक गांवों में से लगभग 13 हजार गांवों में बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर लिया गया है और मई 2018 तक बाकी बचे गांवों में भी बिजली पहुंचाने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काले-धन के खिलाफ चरणबद्ध व वैज्ञानिक तरीके से अभियान की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में काले-धन के खिलाफ एसआईटी गठित करने का निर्णय लिया, फिर काले-धन के सिंगापुर-मॉरीशस रूट को बंद किया गया। इसके बाद ओपन डिक्लेरेशन स्कीम लॉन्च की गई, सेल कंपनियों के खिलाफ अंकुश लगाया गया और इसके पश्चात् बेनामी संपत्ति क़ानून को अमल में लाकर काले-धन पर ज़ोरदार प्रहार किया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव को काले-धन के गिरफ्त से छुड़ाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा कैश में लिए जाने वाले चंदे की सीमा को घटाकर 2000 रुपये कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद काले-धन पर अंकुश लगाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक तरीके से कदम कभी उठाये नहीं गए।

श्री शाह ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वायल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया, खाद के दाम को कम करना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, ई-मंडी जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा है जो अप्रतिम है। उन्होंने कहा कि स्टैंट के दाम कम किये जाने और जेनेरिक दवाओं के माध्यम से देश के करोड़ों गरीबों के लिए स्वास्थ्य लाभ लेना आसान हुआ है।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में केन्द्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 28,04,67 करोड़ रुपये थी, जबकि मोदी सरकार के समय 14वें वित्त आयोग में यह बढ़कर 71,09,66 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 13वें वित्त आयोग में यूपी को 24 हजार करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई थी, जिसे मोदी सरकार ने दोगुना बढ़ाकर 48 हजार करोड़ रुपया कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में भी वृद्धि करते हुए 1597 करोड़ रुपये की तुलना में 2797 करोड़ रुपये आवंटित किये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय उत्तर प्रदेश को लोकल बॉडीज ग्रांट के तौर पर केवल 523 करोड़ रुपये मिलते थे, जबकि मोदी सरकार ने इसमें 88 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि करते हुए 4,60,26 करोड़ रुपये आवंटित करने का काम किया। उन्होंने कहा कि केवल इन चारों विभागों में ही उत्तर प्रदेश को 8,07,7 89 करोड़ रुपये दिए गए जो कांग्रेस सरकार की तुलना में लगभग ढाई गुना है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यूपी में केन्द्रीय योजनाओं की बात करें तो मुद्रा योजना में प्रदेश के 72 लाख लाभार्थियों को आसान शर्तों में ऋण उपलब्ध कराये गए। स्मार्ट सिटी में अब तक 571 करोड़ रुपये आवंटित किये गए, अमृत मिशन के लिए 11521 करोड़, गोरखपुर में यूरिया प्लांट के लिए 6000 करोड़, आठ हाइवे के लिए 8000 करोड़, स्वच्छ भारत अभियान के लिए 168 करोड़, बनारस ट्रौमा सेंटर के लिए 150 करोड़, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट के लिए 617 करोड़, रेल विकास के लिए 36 हजार करोड़, नमामि गंगे के लिए 3668 करोड़, गंगा सीवरेज के लिए 7600 करोड़, लखनऊ मेट्रो के लिए 6880 करोड़, नेशनल वाटर मिशन के लिए 169 करोड़, एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 700 करोड़, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान के लिए 136 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 2100 करोड़ और आवास योजना, सिंचाई सुविधा एवं बाढ़ प्रबंधन योजनाओं में भी करोड़ों रुपये आवंटित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि इन योजनाओं में दी गई राशि को जोड़ दिया जाय तो यह कुल मिला कर 139052 करोड़ रुपये होती है जो केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त है।

श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में साढ़े चार करोड़ जन-धन खाते खोले गए, 25 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 59 लाख गैस कनेक्शन वितरित किये गए, उज्जवल डिस्कॉम योजना के अंतर्गत यूपी को 33 हजार करोड़ रुपये और दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश को दी जाने वाली सहायता को जोड़ दिया जाय तो यह यूपीए सरकार की तुलना में लगभग 2.3 गुना ज्यादा है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के

नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार के गठन के बाद कई सेक्टरों में व्यापक सुधार देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट बैठक में किसानों के ऋण माफ़ कर दिए गए। लगभग 38 लाख टन गेहूं की खरीदी अब तक कर ली गई है जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के बकाये का 90.68 प्रतिशत का भुगतान किया जा चुका है जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि पहले सपा-बसपा के मिलीभगत के कारण गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान नहीं हो पाता था। उन्होंने कहा कि बिजली और सिंचाई के क्षेत्र में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ■

'खट्टर सरकार ने राजनीति की संस्कृति बदली'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 2 अगस्त को डॉ. राधाकृष्णन ऑडिटोरियम, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक (हरियाणा) में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, सिद्धांतों और कार्यपद्धति पर विस्तार से चर्चा की। विदित हो कि श्री शाह देश के सभी राज्यों में कुल 110 दिनों के अपने विस्तृत प्रवास कार्यक्रम के तहत तीन दिवसीय दौरे पर हरियाणा में थे। इससे पहले बहादुरगढ़ से रोहतक जाने के क्रम में प्रदेश की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत किया। रोहतक पहुंचने पर श्री शाह ने तिलयार कन्वेंशन सेंटर, तिलयार (रोहतक) में प्रदेश पदाधिकारियों, कोर ग्रुप के सदस्यों, मोर्चा अध्यक्षों, जिला अध्यक्षों, जिला महासचिवों और सभी बोर्ड एवं निगम के चेयरपर्सन के साथ बैठक की। तत्पश्चात् उन्होंने प्रकोष्ठ और मोर्चा अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श किया।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के विकास व गरीब-कल्याण के लिए लगभग 106 योजनाओं की शुरुआत की है और इनमें से एक भी योजना ऐसी नहीं है जो किसी एक वर्ग के लिए बनी हो। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा की भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए कई कदम उठाये हैं। 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने हरियाणा के लिए पांच वर्षों में 14,937 करोड़ रुपये राशि आवंटित की, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने हरियाणा के लिए पांच वर्षों में 42,847 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो 13वें वित्त आयोग के मुकाबले लगभग तीन गुनी अधिक है, इसी तरह 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने हरियाणा के लिए ग्रांट इन ऐड के तौर पर 3,670 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने लगभग दुगुनी वृद्धि करते हुए इसके लिए 7,238 करोड़ रुपये निर्धारित किये। उन्होंने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी वृद्धि करते हुए यूपीए सरकार के 711 करोड़ रुपये की तुलना में मोदी सरकार ने

5963 करोड़ रुपये आवंटित किये। उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज ग्रांट के तौर पर यूपीए सरकार ने 13वें वित्त आयोग में 1,533 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने इसमें लगभग चार गुना वृद्धि करते हुए 5,963 करोड़ रुपये आवंटित किये। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने कुल मिलाकर इन योजनाओं में 34,409 करोड़ रुपये की वृद्धि की है जो लगभग ढाई गुना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को केन्द्रीय योजनाओं के लिए 19 हजार करोड़ रुपये और डिस्कॉम के लिए 14,200 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं, इस तरह सभी मदों में तीन साल में मोदी सरकार ने हरियाणा को 67,691 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने श्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा की राजनीति की संस्कृति को बदलने का काम किया है। 'मेरा क्या' की जगह 'हरियाणा का क्या' की संस्कृति विकसित हुई है जो अपने-आप में काफी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं की सरकार नहीं है, बल्कि हरियाणा के एक-एक व्यक्ति की सरकार है। उन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे के बाद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन हुआ है, जो प्रदेश के जन-जन के विकास के लिए काम करती है। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आप सब को विश्वास दिलाता हूं कि श्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हम हरियाणा को भी विकास के पथ पर तेज गति से अग्रसर करेंगे और इसे देश का एक विकसित प्रदेश बनायेंगे।

'हरियाणा में सबकी सरकार'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 अगस्त को तिलयार कन्वेंशन सेंटर, रोहतक (हरियाणा) में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार और हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार की उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के 13वें वित्त आयोग की तुलना में मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में हरियाणा को लगभग ढाई गुनी ज्यादा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने हरियाणा के लिए पांच वर्षों में 14,937 करोड़ रुपये राशि आवंटित की, जबकि 14वें वित्त आयोग में मोदी सरकार ने हरियाणा के लिए पांच वर्षों में 42,847 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है जो 13वें वित्त आयोग के मुकाबले लगभग तीन गुनी अधिक है। इसी तरह 13वें वित्त आयोग में कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार ने हरियाणा के लिए ग्रांट इन ऐड के तौर पर 3,670 करोड़ रुपये दिए थे जबकि मोदी सरकार ने लगभग दुगुनी वृद्धि करते हुए इसके लिए 7,238 करोड़ रुपये निर्धारित किये। उन्होंने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी वृद्धि करते हुए यूपीए सरकार के 711 करोड़ रुपये की तुलना में मोदी सरकार ने 5963 करोड़ रुपये आवंटित किये। उन्होंने कहा कि लोकल बॉडीज ग्रांट के तौर पर यूपीए सरकार ने 13वें वित्त आयोग में 1,533 करोड़ रुपये दिए थे, जबकि मोदी सरकार ने इसमें लगभग चार गुना वृद्धि करते हुए 5,963 करोड़ रुपये आवंटित किये। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार ने कुल मिलाकर इन योजनाओं में 34,409 करोड़ रुपये की वृद्धि की है जो लगभग ढाई गुना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को केन्द्रीय योजनाओं के लिए 19 हजार करोड़ रुपये और डिस्कॉम के लिए 14,200 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिए गए हैं। इस तरह सभी मदों में तीन साल में मोदी

सरकार ने हरियाणा को 67,691 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य में 1.26 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये गए हैं, 61 लाख जन-धन खाते खोले गए हैं, तीन लाख एलपीजी सिलिंडर बांटे गए हैं।

श्री शाह ने कहा कि हरियाणा की मनोहरलाल खट्टर सरकार ने राज्य को एक पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अब तक या तो किसी परिवार की सरकार चलती थी या फिर किसी जाति की, बहुत लंबे अरसे से हरियाणावासियों ने हरियाणा की सरकार का अनुभव नहीं किया था। पहली बार मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा में सबकी सरकार आई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार जीरो करप्शन के साथ हरियाणा में पारदर्शी भर्तियां हुई हैं, शिक्षा विभाग में भी ऑनलाइन ट्रांसफर लागू किया गया है। लगभग 35000 लोगों को ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया गया है और इसमें लगभग 91 प्रतिशत लोगों को अपने मनपसंद स्थान पर प्रतिनियुक्ति मिली है। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार के अथक प्रयासों से हरियाणा में लिंगानुपात सुधरा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने स्वर्ण जयन्ती वर्ष में प्रदेश को किरोसिन मुक्त हरियाणा का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटराईज्ड करके भ्रष्टाचार को ख़त्म किया गया है। उन्होंने कहा कि ई-पंजीकरण, ई-स्टाम्प का अभिनव प्रयोग हरियाणा में हुआ है और सरकार द्वारा एक ही छत के नीचे सारी औद्योगिक स्वीकृतियों को भी पूरा करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर खेत को सिंचाई के लिए

पानी देने का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशानिर्देशन में और श्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा विकास की नई कहानी लिखेगा और एक विकसित प्रदेश के रूप में स्थापित होगा।

भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन

'राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है और अंत्योदय लक्ष्य'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 4 अगस्त को रोहतक (हरियाणा) में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं से पार्टी को प्रदेश के हर बूथ पर मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने रोहतक को ऐतिहासिक भूमि बताते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती का स्मरण किया और कहा कि देश की सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का योगदान अमूल्य है।

श्री शाह ने कहा कि यह बड़े हर्ष की बात है कि हरियाणा में कार्यकर्ता सम्मेलन एक ऐसे समय पर हो रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी वैभव के इस शिखर पर खड़ी है - आज देश के 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, पांच अन्य राज्यों में भाजपा एवं सहयोगियों की सरकारें, 1387 विधायक हैं, 330 से अधिक सांसद हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। उन्होंने कहा कि विजय कभी-कभी आलस्य का निर्माण करती है। उन्होंने कहा कि विजय के दो परिणाम होते हैं - एक आलस्य का निर्माण और दूसरा, विजय की भूख का और प्रबल होना, यह भाजपा कार्यकर्ताओं को तय करना है कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि विजय पार्टी कार्यकर्ताओं में आलस्य का निर्माण करता है तो पार्टी कभी अपने सर्वोच्च को नहीं पा सकती।

श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है और अंत्योदय हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जब तक इस देश का एक भी व्यक्ति भूखा है, जब तक एक भी बच्ची पढ़ाई से वंचित है, जब तक एक भी खेत पानी से वंचित है तब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आराम का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि हमें एक ऐसे देश की रचना करनी है, जिसे पूरा विश्व अपना मार्गदर्शक स्वीकार करे, तो हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को इस दिशा में चिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम विचारधारा पर आधारित पार्टी हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा में श्री मनोहरलाल खट्टर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, लेकिन संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना बाकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मशती वर्ष में हम हरियाणा में एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी के निर्माण का लक्ष्य रखें, जो अपराजेय हो और यदि ऐसी पार्टी बनाने का लक्ष्य पाना है तो हर बूथ को भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सौ से अधिक पार्टी कार्यकर्ता पूर्णकालिक के रूप में 6 महीने और साल भर के लिए बूथ-स्तर पर पार्टी की मजबूती के लिए काम करने निकले हैं, हमें राज्य के सभी 90 विधान सभाओं के हर बूथ पर पार्टी को मजबूत बनाना है।

श्री शाह ने कहा कि हरियाणा में एक परंपरा बन गई थी कि सरकार व्यक्तियों की होती है, परिवार और जातियों की होती है। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हरियाणा में ऐसी सरकार चलायें, जो किसी परिवार, जाति या व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम करने वाली सरकार हो। आज हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार सबकी सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खट्टर सरकार ने हर विभागों में होने वाली भर्तियों के अंदर पारदर्शिता बरती है और किसी को घूस नहीं देना पड़ा, यह हमारे लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करते हुए इसे कम्पयूटराईज्ड किया गया, जिसके फलस्वरूप 38 हजार फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया गया और करोड़ों का भ्रष्टाचार ख़त्म किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल ने पढ़े-लिखे पंचायत का विरोध किया था, लेकिन हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि हमारी सरकार ने हरियाणा को पढ़ी-लिखी पंचायत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ई-स्टाम्पिंग, ई-पंजीकरण और सिंगल विंडो के जरिये व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। बिजली की स्थिति सुधरी है और प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का जाल बिछाया गया है, साथ ही सीधे हस्तांतरण से भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी सरकार और खट्टर सरकार की उपलब्धियों को राज्य के जन-जन तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के विकास व गरीब-कल्याण के लिए लगभग अंत्योदय के सिद्धांत पर 106 योजनाओं की शुरुआत की है और इनमें से एक भी योजना ऐसी नहीं है, जो किसी एक वर्ग के लिए बनी हो। ये सभी योजनायें सर्वस्पर्शी एवं सर्व-समावेशी हैं। ■

पश्चिम बंगाल प्रदेश के भाजपा मुखपत्र 'कमल बार्ता' का लोकार्पण

पश्चिम बंगाल भाजपा पत्रिका और प्रकाशन विभाग ने 30 जुलाई 2017 को संपन्न प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में राज्य भाजपा मुखपत्र 'कमल बार्ता' का शुभारंभ किया। प्रदेश की नई पत्रिका 'कमल बार्ता' का लोकार्पण प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप घोष, राष्ट्रीय मंत्री श्री राहुल सिन्हा, प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुब्रत चट्टोपाध्याय, भाजपा की पार्टी पत्रिकाएं एवं प्रकाशन विभाग के राष्ट्रीय संयोजक और 'कमल संदेश' के कार्यकारी संपादक डॉ. शिव शक्ति बक्सी, राज्य प्रकाशन विभाग संयोजक श्री प्रणय राय एवं अन्य नेताओं की उपस्थिति में हुआ।

यही नहीं, 29 जुलाई 2017 को पार्टी कार्यालय में विभाग की एक बैठक प्रदेश महामंत्री (संगठन) श्री सुब्रत चट्टोपाध्याय तथा महामंत्री श्री सांतनु घोष एवं विभाग संयोजक श्री प्रणय राय की उपस्थिति में संपन्न हुई। साथ ही, पत्रिका से जुड़े बुद्धिजीवियों से विचार-विमर्श भी हुआ। डॉ. शिव शक्ति बक्सी ने भी कोलकाता स्थित राज्य भाजपा कार्यालय में संपन्न पश्चिम बंगाल भाजपा पत्रिका और प्रकाशन विभाग की बैठक को संबोधित किया। ■

नव गठित 'असम भाजपा पत्रिका और प्रकाशन विभाग' की प्रथम संगठनात्मक बैठक संपन्न

भाजपा की पार्टी पत्रिकाएं एवं प्रकाशन विभाग के राष्ट्रीय संयोजक और 'कमल संदेश' के कार्यकारी संपादक डॉ. शिव शक्ति बक्सी ने गुवाहाटी, असम में एक अगस्त को संपन्न हुई नव गठित 'असम भाजपा पत्रिका और प्रकाशन विभाग' की प्रथम संगठनात्मक बैठक में भाग लिया। बैठक गुवाहाटी स्थित भाजपा असम प्रदेश मुख्यालय के 'अटल बिहारी वाजपेयी भवन' में संपन्न हुई। इस अवसर पर नए कलेवर में प्रदेश पत्रिका 'बीजेपी बार्ता' को पुनः आरंभ किया गया।

इस बैठक में असम प्रदेश भाजपा संगठन (महामंत्री) श्री फणीन्द्र नाथ शर्मा, महामंत्री श्री दिलीप सैकिया, मंत्री श्री किशोर उपाध्याय, प्रदेश महिला आयोग अध्यक्षा श्रीमती शिकिनि तालुकदार, विभाग

संयोजक डॉ. देवदत्त बरकाताकी और अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया।

बैठक की अध्यक्षता राज्य विभाग संयोजक डॉ. देवदत्त बरकाताकी और संचालन राज्य सह-सहसंयोजक श्री रंजन चक्रवर्ती ने किया। ■

बाढ़ प्रभावित उत्तर-पूर्वी राज्यों को 2000 करोड़ रुपए से अधिक सहायता राशि की घोषणा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अगस्त को बाढ़ प्रभावित उत्तर-पूर्वी राज्यों में राहत, पुनर्वास, पुनर्निर्माण और बाढ़ की स्थिति से निपटने के उपायों के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के राहत पैकेज की घोषणा की। उच्चस्तरीय बैठकों के अंतिम चरण में यह घोषणा की गई, जिसमें प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति और राहत के उपायों की समीक्षा की।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड राज्यों में बाढ़ की स्थिति के बारे में विस्तृत और अलग-अलग समीक्षा बैठकों में हिस्सा लिया। इन राज्यों के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी बैठकों में उपस्थित थे। मिजोरम के मुख्यमंत्री की ओर से एक ज्ञापन भेजा गया था, जो व्यक्तिगत रुप से बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए।

केंद्र सरकार की ओर से केवल बुनियादी क्षेत्र के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि दी जाएगी। इस धनराशि का इस्तेमाल सड़कों, राजमार्गों, पुलों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मरम्मत, रखरखाव और मजबूती के लिए किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की जल ग्रहण क्षमता में सुधार के लिए 400 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी, जिससे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलेगी।

मौजूदा वित्त वर्ष में, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा राहत निधि के केंद्रीय हिस्से के रूप में 600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें से 345 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और शेष धनराशि शीघ्र जारी की जाएगी, ताकि राहत और पुनर्वास कार्य में राज्य की सहायता की जा सके। केंद्र सरकार इस क्षेत्र में लगातार बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु समयबद्ध दीर्घकालिक समाधान के प्रयासों के बीच तालमेल आधारित एक अध्ययन के संचालन के लिए 100 करोड़ रुपए प्रदान करेगी।

भारत भूमि के आठ प्रतिशत हिस्सा वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में देश का एक-तिहाई जल संसाधन मौजूद है। केंद्र सरकार इस क्षेत्र के विशाल जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत निधि के अधीन बाढ़ के कारण मारे गए लोगों के निकट संबंधी को 2,00,000 रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि मंजूर की गई है। ■

सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान

संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. महेश शर्मा ने 31 जुलाई को लोक सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी कि देश में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 2015 की तुलना में 2016 में 12.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें धार्मिक उद्देश्यों के साथ-साथ चिकित्सा के लिए भी सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में घरेलू पर्यटकों की यात्राएं शामिल है। 2015 में 143.2 करोड़ लोगों की तुलना में 2016 में 161.4 करोड़ लोगों ने एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा की।

भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2015 के 2.3 करोड़ से बढ़कर 2016 में 2.5 करोड़ हो गई। कुल मिलाकर 2016 में 2015 की तुलना में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें धार्मिक और चिकित्सा पर्यटन दोनों शामिल हैं। इस वर्ष देश में जनवरी से जून के बीच 48.8 लाख पर्यटक आये, जोकि पिछले वर्ष इसी अवधि में आने वाले पर्यटकों की तुलना में 17.2 फीसदी अधिक है।

भारत के दूसरे पर्यटन सेटेलाइट अकाउंट के अनुसार पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 में कुल अनुमानित योगदान क्रमशः 6.77, 6.76, 6.76 और 6.88 प्रतिशत रहा। गौरतलब है कि पर्यटन के क्षेत्र में वायु / रेल / सड़क होटल और रेस्टोरेंट आदि जैसी सेवाएं शामिल हैं। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने कई कदम उठाए है।

देश में पर्यटन को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं :

- स्वदेश दर्शन - विशिष्ट विषयों पर पर्यटन परिपथों का समन्वित विकास
- तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रसाद) के लिए राष्ट्रीय मिशन
- बाजार के विकास में सहायता और विदेशों में प्रचार और प्रसार
- आईएचएम / एफसीआई / आईआईटीटीएम / एनसीएचएमसीटी को सहायता
- आतिथ्य क्षेत्र सहित देश में प्रचार और प्रसार
- सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम
- कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी ■

रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की

कर्ज होंगे सस्ते

भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 अगस्त को नई रेपो रेट दर की घोषणा करते हुए रेपो रेट में 0.25 बेसिस पाइंट की कमी कर दी। दरअसल, थोक व खुदरा महंगाई दर में कमी के कारण रिजर्व बैंक पर रेपो रेट में कमी करने का दबाव बढ़ गया था। अब रेपो रेट 6.25 फीसदी से घटकर 6 फीसदी हो गया है, वहीं रिवर्स रेपो रेट 5.75 फीसदी हो गया है।

गौरतलब है कि रेपो रेट कम होने से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी क्योंकि मौजूदा समय में महंगाई दर नियंत्रण में है। यही नहीं, रेपो रेट कम होने से ऑटो और होमलोन सेक्टर को फायदा होगा, क्योंकि कर्ज सस्ता होने के बाद लोग ज्यादा संख्या में घर एवं कार खरीदना पसंद करेंगे।

रिज़र्व बैंक ने अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में कहा कि खाद्य और पेय पदार्थों की कीमत, जो नई सीपीआई श्रृंखला में पहली बार मई 2017 में अपस्फीति में आई, जून में दालों, सब्जियों, मसाले और अंडों की कीमतों में साल दर साल गिरावट दर्ज की गई और ज्यादातर अन्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति कम हो गई।

रिज़र्व बैंक ने अपने वक्तव्य में कहा कि घरेलू मोर्चे पर लगातार दूसरे वर्ष दक्षिण-पश्चिमी मानसून के सामान्य और सही वितरण से कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों और ग्रामीण मांग की संभावनाएं उज्ज्वल हुई हैं। 1 अगस्त तक, दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 1 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई और देश के भौगोलिक क्षेत्र के 84 प्रतिशत हिस्से में अधिक से सामान्य बारिश हुई है। खरीफ की बुआई पिछले वर्ष की तुलना में अधिक तेज गति से हुई है जहां गन्ने, पटसन और सोयाबीन की पूरे मौसम की बुआई पूरी हो चुकी है।

रिज़र्व बैंक ने कहा कि कपास और मोटे अनाज की बुआई पिछले वर्ष के स्तर से अधिक हुई है किंतु तिलहन की बुआई पिछड़ी हुई है। कुल मिलाकर, इन गतिविधियों से वर्ष 2017-18 के लिए फसल उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जिन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा पिछले वर्ष में हासिल शीर्ष स्तर की अपेक्षा उच्चतर स्तर पर निर्धारित किया है। इसी बीच रबी विपणन मौसम के दौरान चावल और गेहूं के संबंध में खरीद परिचालन रिकार्ड स्तर तक बढ़ गए हैं, जो अप्रैल-जून 2017 में 36.1 मिलियन टन थे और स्टॉक सितंबर को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए बढ़कर बफर मानदंड के 1.5 गुणा हो गए हैं। ■

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 425 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने 31 जुलाई को अपनी चौथी बैठक में सीवेज से जुड़े बुनियादी ढांचे, घाटों के विकास और शोध के क्षेत्र में 425 करोड़ रुपये की लागत वाली सात परियोजनाओं को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश और बिहार में सीवेज (दूषित जल की निकासी) की तीन-तीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई।

उत्तर प्रदेश में उन्नाव, शुक्लागंज और रामनगर के लिए जल अवरोधन यानी पानी का बहाव रोकने, बहाव में परिवर्तन और एसटीपी (सीवेज शोधन संयंत्र) से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन तीनों परियोजनाओं का उद्देश्य 29 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) की सीवेज शोधन क्षमता (उन्नाव में 13 एमएलडी, शुक्लागंज में 6 एमएलडी और रामनगर में 10 एमएलडी) सृजित करना है। इन परियोजनाओं पर कुल मिलाकर 238.64 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

वहीं, बिहार में सुल्तानगंज, नौगछिया और मोकामा में 175 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली तीन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं से 27 एमएलडी की सीवेज शोधन क्षमता (सुल्तानगंज में 10 एमएलडी, मोकामा में 8 एमएलडी और नौगछिया में 9 एमएलडी) सृजित होगी।

इन सभी छह परियोजनाओं पर आने वाली परिचालन और रख-रखाव लागत को केन्द्र सरकार 15 साल तक वहन करेगी। इन परियोजनाओं के लिए 100 फीसदी केंद्रीय सहायता दी जाएगी। यहां पर इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि उन्नाव और सुल्तानगंज परियोजनाओं का क्रियान्वयन हाइब्रिड वार्षिकी पर आधारित पीपीपी मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, जिसके तहत पूंजीगत लागत का 60 प्रतिशत एसटीपी का निर्माण करने वाले ठेकेदार को अगले 15 वर्षों की अवधि के दौरान दिया जाएगा। ठेकेदार को इस राशि का भुगतान शोधित अपशिष्ट जल के अपेक्षित मानकों पर खरा उतरने से संबंधित उसके कार्य प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

पानी और तलछट दोनों में ही गंगा नदी के गैर-दुर्गंधयुक्त गुणों को समझने के लिए 4.96 करोड़ रुपये की लागत वाले एक शोध अध्ययन को भी मंजूरी दी गई थी। यह अध्ययन राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान (एनईईआरआई) द्वारा किए गए शोध कार्य के एक विस्तार के रूप में होगा, ताकि नदियों के पानी में निहित विशेष गुणों के बारे में पता लगाया जा सके। इस शोध के तहत इन विशेष गुणों के पीछे के वैज्ञानिक कारणों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि इन खूबियों को अक्षुण्ण बनाए रखने की रणनीति तैयार की सके। ■

यह समय परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों और प्राइवेट इक्विटी संस्थानों के लिए बेजोड़ अवसर है : अरुण जेटली

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि धनशोधन और दिवाला संहिता फ्रेमवर्क और सरकार द्वारा समाधान पर बल देने से परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों (एआरसी) और निजी इक्विटी (पीई) संस्थानों के लिए बेजोड़ अवसर पैदा हुए हैं। प्रमुख एआरसीज़ और निजी इक्विटी संस्थानों के साथ एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि खराब/फंसे हुए घोषित किए गए खातों का अभी भी अंतर्निहित मूल्य है। उन्होंने कहा कि यदि इन खातों को बहाल कर दिया जाता, तो वे अनिवार्यतः उत्पादक परिसम्पत्तियां होते और न केवल अतिरिक्त रोजगार पैदा करते, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन मी भी योगदान करते। इसके लिए जरूरी था कि समय रहते उपाय किए जाते, पारदर्शी मूल्य अन्वेषण और सही प्रबंधन किया जाता।

श्री जेटली ने पिछले 18 महीनों के दौरान किए गए वैधानिक और नियामक परिवर्तनों पर प्रकाश डाला, जिनसे परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के लिए एक सक्षम और सहायक प्रचालनगत वातावरण का निर्माण हुआ है और फंसी हुई परिसम्पत्तियों का एआरसीज़/विशेष स्थिति निधियों द्वारा अधिग्रहण संभव हो पाया। इन उपायों में प्रायोजकों द्वारा शत-प्रतिशत स्वामित्व, एआरसीज़ में शत-प्रतिशत एफडीआई की व्यवस्था करना, एआरसी ट्रस्टों को आयकर से छूट प्रदान करना, स्टांप ड्यूटी से मुक्ति, प्रतिभूति प्राप्तियों की खरीद फरोख्त की अनुमति आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में बड़ी संख्या में नई एआरसीज़ ने पंजीकरण की मांग की और उन्हें पंजीकृत किया गया। उन्होंने कहा कि बाजार में ऐसी कम्पनियों

की संख्या बढ़ना इस बात का संकेत है कि इस क्षेत्र में रुचि बढ़ी है। उन्होंने कहा कि इससे बैंकों के लिए भी यह अवसर पैदा हुआ है कि वे उनके लिए पूर्ण प्रावधान करते हुए तत्संबंधी स्ट्रैस को आफलोड करें।

विचार-विमर्श के दौरान एआरसी और पीई संस्थानों ने सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों की सराहना की। बैठक में एआरसीज़/पीई निधियों द्वारा लक्षित मामलावार समाधान की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि इन संस्थाओं की प्रचालनगत सक्षमता बहुत अधिक है। पूंजी जुटाने और नियोजित करने की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया। यह सुझाव दिया गया कि किसी पृथक बैंक द्वारा स्वयं के ऋण खाते को बेचने की बजाए किसी कंसोर्टियम द्वारा परियोजना ऋण की बिक्री अधिक कारगर हो सकती है, जिससे समय पर ऋण संग्रह सुनिश्चित किया जा सकता है। एआरसीज़ और पीई फंड्स की गतिविधियां बढ़ाने के बारे में भी सुझाव दिए गए।

प्राप्त जानकारी का संज्ञान लेते हुए श्री जेटली ने यह माना कि सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा एआरसीज़ और विशेष स्थिति फंड्स को पहुंचाई गई सुविधाओं का ऋण समाधान की स्थिति पर अनुकूल असर पड़ा है। नतीजतन बैंकों, एआरसीज़, पीई, परिसम्पत्ति प्रबंधन कम्पनियों और समाधान व्यवसायियों के बीच सहयोग से नए निवेश, नए रोजगार और अतिरिक्त मांग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ■

कैबिनेट ने दी ब्रिक्स कृषि शोध प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के बीच एमओयू को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 2 अगस्त को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स कृषि शोध प्लेटफॉर्म (ब्रिक्स-एआरपी) की स्थापना के लिए भारत और ब्रिक्स के अन्य सदस्य देशों के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र (एमओयू) को अपनी पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि रूस के ऊफा में 9 जुलाई, 2015 को आयोजित सातवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स कृषि अनुसंधान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा जो पूरे विश्व को एक उपहार होगा। यह केन्द्र ब्रिक्स के सदस्य देशों में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृषि क्षेत्र में नीतिगत सहयोग के जरिए सतत कृषि विकास एवं गरीबी उन्मूलन को बढ़ावा देगा।

ब्रिक्स देशों में छोटे किसानों द्वारा की जाने वाली खेती के लिए प्रौद्योगिकियों सहित कृषि अनुसंधान नीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं क्षमता निर्माण के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए भारत के गोवा में 16 अक्टूबर, 2016 को आयोजित आठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के मंत्रियों द्वारा कृषि अनुसंधान प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये थे।

विश्व में भूखमरी, गरीबी एवं विषमता, विशेष रूप से किसानों और गैरकिसानों की आय में विषमता से जुड़े मसलों को सुलझाने और कृषि व्यापार, जैव सुरक्षा एवं जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक कृषि आधारित सतत विकास हेतु प्राकृतिक वैश्विक प्लेटफॉर्म के रूप में ब्रिक्स–कृषि अनुसंधान प्लेटफॉर्म (एआरपी) की प्रस्तावना की गई है। ■

सदोष शिक्षा पद्धति बेकारी के लिए जिम्मेदार

– पं. दीनदयाल उपाध्याय

हमारी सदोष शिक्षा पद्धति भी बेकारी के लिए बहुत कुछ ज़िम्मेदार है। आज तो बेकारी का जो बढ़ा हुआ स्वरूप दिखाई देता है, वह शिक्षित मध्यम-वर्ग की बेकारी है। यह वर्ग एक विशेष प्रकार की रहन-सहन का आदी है तथा केवल कलम का ही काम कर सकता है। शिक्षा में आज हाथ के काम को कोई स्थान नहीं। इतना ही नहीं, आज का पठित युवक हाथ के काम से घृणा भी करने लगता है। इसका कारण यह है कि अंग्रेजी के माध्यम के द्वारा शिक्षा देने के कारण हमारे यहां का शिक्षित नवयुवक समाज से अलग एक वर्ग बन जाता है। उसकी अनुभूतियां समाज से भिन्न हो जाती हैं। वह अपने अनपढ़ पूर्वजों के विचारों को, उनकी रहन-सहन की पद्धति को, उनकी सादगी को नीची निगाह से देखता है। उनके पेशे को भी वह छोटा समझने लगता है। फलतः आज लाखों नवयुवक ऐसे हो गए हैं, जो अपना पुश्तैनी पेशा छोड़ चुके हैं। वे सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी की तलाश में इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, किंतु न तो कोई हाथ का काम करने की उनमें योग्यता है और न इच्छा। अतः आवश्यकता है कि हमारी शिक्षा को भारतीय बनाया जाए और उसका माध्यम मातृभाषा रखी जाए। मातृभाषा

हमारे यहां का शिक्षित नवयुवक समाज से अलग एक वर्ग बन जाता है। उसकी अनुभूतियां समाज से भिन्न हो जाती हैं। वह अपने अनपढ़ पूर्वजों के विचारों को, उनकी रहन-सहन की पद्धति को, उनकी सादगी को नीची निगाह से देखता है। उनके पेशे को भी वह छोटा समझने लगता है। फलतः आज लाखों नवयुवक ऐसे हो गए हैं, जो अपना पुश्तैनी पेशा छोड़ चुके हैं। वे सरकारी या गैर-सरकारी नौकरी की तलाश में इधर-उधर मारे-मारे फिरते हैं, किंतु न तो कोई हाथ का काम करने की उनमें योग्यता है और न इच्छा।

के माध्यम से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को गांवों में रहने में कठिनाई नहीं होगी और न वह हाथ के काम से दूर भागेगा।

अक्षर और साहित्य के ज्ञान के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी को किसी-न-किसी प्रकार की औद्योगिक शिक्षा दी जाए। औद्योगिक शिक्षा की दृष्टि से यद्यपि विचार बहुत दिनों से हो रहा है, किंतु अभी तक सिवाय कुछ औद्योगिक शिक्षा केंद्रों के खोलने के साधारण

शिक्षा का मेल औद्योगिक शिक्षा से नहीं बिठाया है। टेक्निकल और वोकेशनल शिक्षा केंद्रों में भी शिक्षा प्राप्त नवयुवक इस योग्य नहीं बन पाते कि वे स्वयं कोई कारोबार शुरू कर सकें। वे भी नौकरी की ही तलाश में घूमते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जाती है, वह उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के अयोग्य बना देती है।

अतः आवश्यक तो यह होगा कि गांवों के धंधे, खेती और व्यापार के साथ हमें शिक्षा का मेल बैठाना होगा। प्रथमतः शिक्षा की प्रारंभिक एवं माध्यमिक अवस्थाओं में हमें विद्यार्थी को उसके घरेलू धंधे के वातावरण से अलग करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम ऐसा प्रबंध करें कि वह उस वातावरण में अधिक-से-अधिक रह सके तथा अज्ञात रूप से वह धंधा सीख सके। धीरे- धीरे हमें यह भी प्रयत्न करना होगा कि वह अपने अभिभावकों का सहयोगी बन सके। माध्यमिक शिक्षा समाप्त करने तक नवयुवकों को अपना धंधा भी आ जाना चाहिए। हो सकता है कि उस धंधे की योग्यता के प्रमाण-पत्र की भी हमें कुछ व्यवस्था करनी पड़े। माध्यमिक शिक्षा तक कुशाग्र बुद्धि सिद्ध होने वाले नवयुवकों के लिए आगे शिक्षा का प्रबंध उनकी रुचि के अनुसार किया जाए। संक्षेप में शिक्षा की अवधि में बल अक्षर ज्ञान और साहित्य शिक्षा पर न होकर औद्योगिक शिक्षा पर से होना चाहिए तथा उसके अनुरूप ही संपूर्ण पद्धति की रचना करनी चाहिए।

बेकारी के मौलिक कारणों को तो दूर करने की व्यवस्था करनी ही होगी, किंतु आज हमें कुछ-न-कुछ तात्कालिक उपचार भी करना होगा। हां हमारा यह उपचार उसी दिशा में हो, जिस ओर हम मूल समस्या के निराकरण के लिए चल रहे हैं। तात्कालिक उपायों के लिए देश में सभी दलों की ओर से मांग की जा रही है तथा शासन की ओर से भी कुछ कार्यक्रम एवं योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आगरा अधिवेशन में बेकारी की समस्या के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया तथा यह मांग की गई कि पंचवर्षीय योजना में इस दृष्टि से

परिवर्तन किया जाए। प्रस्ताव में राज्य सरकारों से कुटीर एवं छोटे उद्योगों की ओर विशेष ध्यान देने की भी मांग की गई।

कांग्रेस के प्रस्ताव के पश्चात् योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि उसमें मौलिक रूप से कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं। हमें उसने एक एकादश सूत्रीय कार्यक्रम अवश्य प्रस्तुत किया, जिसमें अधिकांश पुरानी बातों को दुहरा दिया। योजना आयोग का कार्यक्रम निम्नलिखित है-

1. व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों को छोटे-छोटे उद्योग प्रारंभ करने के लिए 'उद्योगों को राज्य के विधान' या इस प्रकार के अन्य विधानों के अंतर्गत सहायता देना।
2. जिन क्षेत्रों में जनशक्ति की कमी है उनमें शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना। ऐसे कई क्षेत्र हैं, जिनमें योग्य व्यक्तियों के अभाव के कारण पंचवर्षीय योजना के कार्य में रुकावट आ रही है। विस्तृत शिक्षा की सुविधाएं इस अभाव की पूर्ति करेंगी तथा अर्ध-शिक्षित कामगारों को नई नौकरियों का अवसर प्रदान करेंगी।
3. राज्य सरकार एवं अन्य जन आयोगों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का क्रय करके कुटीर और छोटे उद्योगों को सक्रिय प्रोत्साहन देना।
4. नगर पालिकाओं, अन्य संस्थाओं तथा सेवा संस्थाओं को शहरों में प्रौढ़ पाठशालाएं खोलने के लिए सहायता देना। देहातों में एक-अध्यापक शालाएं खोलना।
5. प्रस्तावित राष्ट्रीय विस्तार योजना को साहस के साथ हाथ में लेना, क्योंकि यह गांवों की अर्थव्यवस्था के विकास एवं पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी की समस्या के हल के लिए आवश्यक है।
6. थल यातायात का विकास करना। प्रचलित लाइसेंस-व्यवस्था का, थल यातायात का विकास करने की दृष्टि से, विशेषकर गैर-सरकारी साधनों से, पुनः विचार करना।
7. देहातों में गंदे क्षेत्रों की सफाई एवं छोटी आय के लोगों के लिए मकान बनाने की योजनाओं को कार्यान्वित करना।
8. गैर-सरकारी गृह निर्माण को प्रोत्साहन देना।
9. पुरुषार्थी बस्तियों को, जिनमें घोर बेकारी है, योजनाबद्ध सहायता देना, जिससे वे ठीक तरह से बस सकें।
10. गैर-सरकारी तौर पर शक्ति (बिजली) पैदा करने की योजनाओं को प्रोत्साहित करना। अभी कई नगरों में बिजली की कमी है, जिससे उद्योगों के विकास एवं लोगों को रोजगार देने में बाधा पहुंचती है। राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति-योजनाओं पर विचार करे तथा जो पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र में नहीं आतीं, उन्हें केंद्र के पास भेजे।
11. काम और शिक्षा-केंद्रों की स्थापना।

उपर्युक्त कार्यक्रम में यद्यपि अनेक सुझाव दिए गए हैं, किंतु समस्या को मौलिक रूप से दूर करने का प्रयत्न नहीं किया गया। साथ ही ये ऐसे सुझाव हैं, जो सरकारों ने समय-समय पर कई बार कहे हैं, किंतु जिन पर कभी अमल नहीं किया गया। यद्यपि योजना आयोग ने यह माना है कि शिक्षित बेकारों की संख्या बहुत अधिक है, किंतु शिक्षा की पद्धति में सुधार की दृष्टि से कुछ भी नहीं किया गया। फिर भी उसका प्रयत्न सराहनीय है।

शासन ने इस दृष्टि से कुछ व्यावहारिक कार्यक्रमों की भी घोषणा की है। 12 करोड़ रुपया लगाकर शिक्षा-विस्तार की दृष्टि से एक अध्यापक स्कूल खोलने का विचार है, जिनमें 80,000 पढ़े-लिखे लोगों को काम मिल सकेगा। 500 करोड़ की पूंजी से एक उद्योग विकास कॉरपोरेशन बनाया जा रहा है, जो छोटे-छोटे उद्योगों को सहायता देगा। किंतु यह 500 करोड़ रुपया कहां से आएगा, इस संबंध में समाप्त होने वाली अनेक योजनाओं के समान यह भी कागजी योजना मात्र रह जाएगी। गांवों में स्कूल खोलने की योजना भी अच्छी है, किंतु जो स्कूल खुले हैं, वे भी ठीक चल रहे हैं या नहीं, यह तो देखना होगा। जिला बोर्डों के अनेक स्कूल धन के अभाव में बंद हो रहे हैं। उनके अध्यापक बेकार होते जा रहे हैं। अतः कारीगरों को बेकार बनाकर बेकारों को काम देना केवल स्थान परिवर्तन मात्र होगा। ■

(दीनदयाल समग्र, खंड-3 से साभार)

शंघाई में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की सातवीं बैठक संपन्न

ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों की सातवीं बैठक शंघाई में 1-2 अगस्त को हुई। बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ। इसमें विश्व व्यापार संगठन में जनसंपर्क अधिकारी और राजदूत जे एस दीपक भी शामिल थे। बैठक की अध्यक्षता चीन के वाणिज्य मंत्री ज़ोंग शन ने की। दक्षिण अफ्रीका के व्यापार और उद्योग मंत्री रोब डेविस, ब्राजील के उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य एवं सेवा सचिव मारसेलो माइया टवेयर्स डी अराउजो और रूस के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम ओरेश्किन भी अपने-अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में शरीक हुए।

ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों ने 2 अगस्त पूर्वाह्न चीन के उप-प्रधान मंत्री वांग यंग से औपचारिक मुलाकात की। बैठक से हटकर 1 अगस्त पूर्वाह्न चीन के वाणिज्य मंत्री और भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के बीच द्वी-पक्षीय बैठक हुई।

बैठक के बाद निम्नलिखित दस्तावेज स्वीकार किए गए:

- सातवें ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों का संयुक्त बयान
- ब्रिक्स देशों में सेवाओं में व्यापार पर सहयोग की रूपरेखा
- ब्रिक्स ई-कामर्स सहयोग पहल
- ब्रिक्स आईपीआर सहयोग दिशा-निर्देश
- ब्रिक्स देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने का प्रारूप
- ब्रिक्स मॉडल ई-पोर्ट नेटवर्क के संदर्भ की शर्तें
- ब्रिक्स निवेश सुविधा की रूपरेखा ■

श्री अरबिंदो

(1872-1950)

शत-शत नमन!

श्री अरबिंदो का मूल नाम अरबिंदो घोष है, किंतु उन्हें अरविंद भी कहा जाता है। आधुनिक काल में भारत में अनेक महान् क्रांतिकारी और योगी हुए हैं, अरबिंदो घोष उनमें अद्वितीय हैं। अरविंदो घोष कवि और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष का दर्शन प्रतिपादित किया। अरविंद को भारतीय एवं यूरोपीय दर्शन और संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। श्री अरविंद का मानना है कि इस युग में भारत विश्व में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहा है तथा भविष्य में भी निभायेगा। उनके दर्शन में जीवन के सभी पहलुओं का समावेश है। उन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। संस्कृति, राष्ट्रवाद, राजनीति, समाजवाद आदि साहित्य, विशेषकर काव्य के क्षेत्र में उनकी कृतियां बहुचर्चित हुई हैं।

अरबिंदो घोष का जन्म बंगाल के कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में एक सम्पन्न परिवार में 15 अगस्त, 1872 को हुआ। उनके पिता का नाम डॉक्टर कृष्ण धन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी था। अरबिंदो घोष की शिक्षा दार्जिलिंग में ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में प्रारम्भ हुई और उन्हें आगे की स्कूली शिक्षा के लिए इंग्लैण्ड भेज दिया गया। इंग्लैण्ड में अरबिंदो घोष की भेंट बड़ौदा नरेश से हुई। बड़ौदा नरेश अरबिंदो की योग्यता देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अरबिंदो

श्री अरबिंदो जी का दृढ़ विश्वास था कि संसार के दुःख का निवारण आत्मा के विकास से हो सकता है जिसकी प्राप्ति केवल योग द्वारा ही संभव है। वे मानते थे कि योग से ही नई चेतना आ सकती है।

को अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त कर लिया। वह बड़ौदा कॉलेज में प्रोफेसर बने और फिर बाद में वाइस प्रिंसीपल भी बने। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां पर वे तीन आधुनिक यूरोपीय भाषाओं के कुशल ज्ञाता बन गए। 1892 में भारत लौटने पर उन्होंने बड़ौदा, वर्तमान वडोदरा और कोलकाता में विभिन्न प्रशासनिक व प्राध्यापकीय पदों पर कार्य किया।

अरबिंदो के लिए 1902 से 1910 के वर्ष हलचल भरे थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया था।

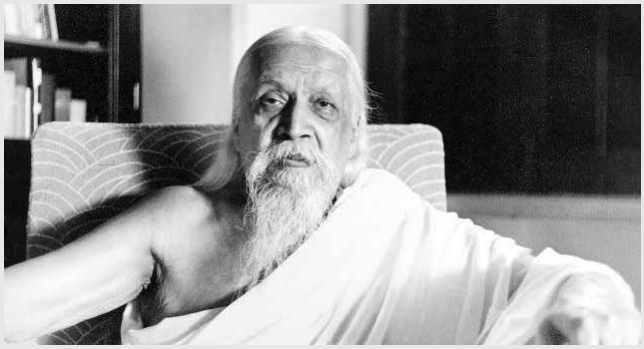

बड़ौदा कॉलेज की नौकरी छोड़कर वह कोलकाता चले गए और कोलकाता के 'नेशनल कॉलेज' के प्रिंसीपल बने। इस समय तक उन्होंने 'सादा जीवन और उच्च विचार' जीवन अपना लिया। उन पर रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के साहित्य का बहुत गहन प्रभाव हुआ। सन् 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में बंगाल के दो टुकड़े कर दिए, ताकि हिन्दू और मुसलमानों में फूट पड़ सके। इस बंग-भंग के कारण बंगाल में जन जन में असंतोष फैल गया। रवीन्द्रनाथ ठाकुर और अरबिंदो घोष ने इस जन आंदोलन का नेतृत्व किया। 1906 से 1909 तक सिर्फ तीन वर्ष प्रत्यक्ष राजनीति में रहे। इसी में देश भर के लोगों के प्रिय बन गए। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस लिखते है- जब मैं 1913 में कलकत्ता आया, अरबिंदो तब तक किंवदंती पुरुष हो चुके थे। जिस आनंद तथा उत्साह के साथ लोग उनकी चर्चा करते शायद ही किसी की वैसी करते। दो वर्ष के बाद ब्रिटिश भारत से भागकर उन्होंने दक्षिण-पूर्वी भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश पाण्डिचेरी में शरण ली, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन पूरी तरह से अपने दर्शन को विकसित करने में लगा दिया। उन्होंने वहां पर आध्यात्मिक विकास के अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में एक आश्रम की स्थापना की, जिसकी ओर विश्व भर के छात्र आकर्षित हुए।

पांडिचेरी आने के बाद वे सांसारिक कार्यों से अलग होकर आत्मा की खोज में लग गए। पांडिचेरी आने के बाद अरबिंदो घोष अंत तक योगाभ्यास करते रहे और उन्हें परमात्मा से साक्षात्कार की अनुभूति हुई। उनका दृढ़ विश्वास था कि संसार के दुःख का निवारण आत्मा के विकास से हो सकता है जिसकी प्राप्ति केवल योग द्वारा ही संभव है। वे मानते थे कि योग से ही नई चेतना आ सकती है। अरबिंदो घोष की मृत्यु 5 दिसम्बर, 1950 में पाण्डिचेरी में हुई। ■

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चले हैं भारत के कदम

| अरुण जेटली |

क्या 'सुपर पावर' बनने की आकांक्षा रखने वाले किसी भी राष्ट्र को रक्षा उपकरणों के आयात पर निरंतर निर्भर रहना चाहिए अथवा स्वदेश में रक्षा उत्पादन अथवा रक्षा क्षेत्र से जुड़े औद्योगिक आधार की अनदेखी करनी चाहिए? निश्चित तौर पर यह उचित नहीं है। स्वदेश में रक्षा उत्पादन अथवा रक्षा क्षेत्र से जुड़ा औद्योगिक आधार किसी भी देश के दीर्घकालिक सामरिक नियोजन का अभिन्न अवयव है। आयात पर काफी अधिक निर्भरता न केवल सामरिक नीति एवं इस क्षेत्र की सुरक्षा में भारत द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के नजरिए से अत्यंत नुकसानदेह है, बल्कि विकास एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं के मद्देनजर आर्थिक दृष्टि से भी चिंता का विषय है। वैसे तो शक्ति से जुड़े तमाम स्वरूपों को हासिल करने पर ही कोई देश 'सुपर पावर' के रूप में उभर कर सामने आता है, लेकिन सही अर्थों में सैन्य शक्ति ही महान अथवा सुपर पावर के रूप में किसी भी राष्ट्र के उत्थान की कुंजी है।

इतिहास के पन्ने पलटने पर हम पाते हैं कि भारतीय रक्षा उद्योग 200 वर्षों से भी अधिक समय का गौरवमयी इतिहास अपने-आप में समेटे हुए है। ब्रिटिश काल के दौरान बंदूकें और गोला-बारूद तैयार करने के लिए आयुध कारखानों की स्थापना की गई थी। प्रथम आयुध कारखाने की स्थापना वर्ष 1801 में काशीपुर में की गई थी। देश की आजादी से पहले कुल मिलाकर 18 कारखानों की स्थापना की गई थी। वर्तमान में भारत के रक्षा क्षेत्र से जुड़े औद्योगिक आधार में भौगोलिक दृष्टि से देश भर में फैले 41 आयुध कारखाने, 9 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डीपीएसयू), 200 से अधिक निजी क्षेत्र लाइसेंस धारक कंपनियां और बड़े निर्माताओं एवं रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) की जरूरतें पूरी करने वाले कुछ हजार छोटे, मझोले एवं सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं। यही नहीं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की 50 से अधिक रक्षा प्रयोगशालाएं भी देश में रक्षा विनिर्माण की पूरी व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं।

वर्ष 2000 के आसपास यह आलम था कि हमारे ज्यादातर प्रमुख रक्षा उपकरणों और हथियार प्रणालियों का या तो आयात किया जाता था या लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के तहत आयुध कारखानों अथवा रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उन्हें भारत में ही तैयार किया जाता था। देश में एकमात्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास एजेंसी होने के नाते डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी विकास में सक्रिय रूप से योगदान दिया और स्वदेशीकरण के प्रयासों को काफी हद तक पूरक के तौर पर आगे बढ़ाया। अनुसंधान एवं विकास तथा विनिर्माण क्षेत्र में डीआरडीओ और डीपीएसयू के प्रयासों के परिणामस्वरूप देश अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है, जहां हमने लगभग सभी प्रकार के रक्षा उपकरणों और प्रणालियों के निर्माण की क्षमताएं भली-भांति विकसित कर ली हैं। आज एक स्थूल विश्लेषण के अनुसार, हमारी कुल रक्षा खरीद में से 40 प्रतिशत खरीदारी तो स्वदेशी उत्पादन की ही की जाती है। कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर स्वदेशीकरण का एक बड़ा हिस्सा बाकायदा हासिल किया जा चुका है। उदाहरण के लिए, टी-90 टैंक में 74 प्रतिशत स्वदेशीकरण, पैदल सेना से जुड़े वाहन (बीएमपी II) में 97 प्रतिशत स्वदेशीकरण, सुखोई 30 लड़ाकू विमान में 58 प्रतिशत स्वदेशीकरण और कॉनकुर्स मिसाइल में 90 प्रतिशत स्वदेशीकरण हासिल हो चुका है। लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के तहत निर्मित किए जा रहे प्लेटफॉर्मों में हासिल व्यापक स्वदेशीकरण के अलावा हमने अपने स्वयं के अनुसंधान एवं विकास के जरिए कुछ प्रमुख प्रणालियों को स्वदेश में ही विकसित करने में भी सफलता पा ली है। इनमें आकाश मिसाइल प्रणाली, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू विमान, पिनाका रॉकेट और विभिन्न प्रकार के रडार जैसे केंद्रीय अधिग्रहण रडार, हथियारों को ढूंढ निकालने में सक्षम रडार, युद्ध क्षेत्र की निगरानी करने वाले रडार इत्यादि शामिल हैं। इन प्रणालियों में भी 50 से 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशीकरण हासिल किया जा चुका है।

सरकारी विनिर्माण कंपनियों और डीआरडीओ के जरिए हासिल की गई उपर्युक्त प्रगति को देखते हुए अब वह सही समय आ गया था कि भारतीय रक्षा उद्योग के दायरे में निजी क्षेत्र को शामिल करके रक्षा से जुड़े औद्योगिक आधार का समुचित विस्तार किया जाए। वर्ष 2001 में सरकार ने 26 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ रक्षा

निर्माण में निजी क्षेत्र के प्रवेश को बाकायदा अनुमति दे दी। हमने रक्षा क्षेत्र से जुड़े अपने औद्योगिक आधार का विनिर्माण करने और इस तरह अंततः आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में हो रहे सफर को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए देश में उपलब्ध विशेषज्ञता और उद्योग जगत के पूरे स्पेक्ट्रम की क्षमता का दोहन करने हेतु अथक प्रयास किए हैं। वैसे तो वर्ष 2001 में ही निजी क्षेत्र के प्रवेश को अनुमति दे दी गई थी, लेकिन रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 3-4 साल पहले तक नगण्य ही थी और वह भी मुख्यतः आयुध कारखानों और डीपीएसयू को आपूर्ति करने के लिए कलपुर्जों एवं उपकरणों के उत्पादन तक ही सीमित थी। पिछले 3 वर्षों के दौरान लाइसेंसिंग व्यवस्था में उदारीकरण की बदौलत विभिन्न रक्षा वस्तुओं के निर्माण के लिए 128 लाइसेंस जारी किए गए हैं, जबकि उससे पहले पिछले 14 वर्षों में केवल 214 लाइसेंस ही जारी किए गए थे।

चूंकि रक्षा एक क्रेता एकाधिकार क्षेत्र है, जिसमें सरकार ही एकमात्र खरीदार है, अतः ऐसे में घरेलू रक्षा उद्योग की संरचना और विकास सरकार की खरीद नीति के जरिए संचालित हो रहा है। इसलिए सरकार ने देश में ही निर्मित उपकरणों को वरीयता देने के लिए अपनी खरीद नीति को अब पहले के मुकाबले बेहतर बना दिया है। सामरिक प्लेटफॉर्मों जैसे लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, पनडुब्बियों एवं बख्तरबंद वाहनों के निर्माण को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में एक ऐसी सामरिक साझेदारी नीति की घोषणा की है, जिसके तहत चयनित भारतीय कंपनियां प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के जरिए भारत में इस तरह के प्लेटफॉर्मों का निर्माण करने के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ मिलकर संयुक्त उद्यमों की स्थापना कर सकती हैं या अन्य प्रकार की भागीदारियां स्थापित कर सकती हैं। पिछले 3 वर्षों में अपनाई गई नीतियों और पहलों ने अपेक्षित परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। 3 साल पहले वर्ष 2013-14 में कुल पूंजीगत खरीदारी का केवल 47.2 प्रतिशत हिस्सा ही भारतीय विक्रेताओं से खरीदा गया था, जबकि वर्ष 2016-17 में यह बढ़कर 60.6 प्रतिशत हो गया है।

देश में ही रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार लागू किए हैं। इनमें लाइसेंसिंग एवं एफडीआई नीति का उदारीकरण, ऑफसेट संबंधी दिशा-निर्देशों को सुव्यवस्थित करना, निर्यात नियंत्रण प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाना और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को समान अवसर देने से संबंधित मसलों को सुलझाना शामिल हैं।

डीपीएसयू की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। सभी डीपीएसयू और आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) से कहा गया है कि वे एसएमई को अपनी आउटसोर्सिंग बढ़ाएं, ताकि देश के भीतर विनिर्माण की समुचित व्यवस्था विकसित हो सके। डीपीएसयू और ओएफबी को निर्यात के साथ-साथ लागत को कम करके एवं अक्षमताओं को दूर करके अपनी प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाने के लिए भी लक्ष्य दिए गए हैं। हमारे रक्षा शिपयार्डों ने जहाज निर्माण में काफी हद तक स्वदेशीकरण हासिल कर लिया है। आज समस्त जहाजों और गश्ती जहाजों इत्यादि के लिए नौसेना और तटरक्षक द्वारा भारतीय शिपयार्डों को ऑर्डर दिए जा रहे हैं। धीरे-धीरे डीपीएसयू में विनिवेश पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें और अधिक जवाबदेह बनाया जा सके तथा इसके साथ ही उनमें परिचालन दक्षता भी सुनिश्चित की जा सके। पिछले 3 वर्षों में डीपीएसयू और ओएफबी के उत्पादन मूल्य (वीओपी) में लगभग 28 प्रतिशत एवं उत्पादकता में 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जहां तक रक्षा उत्पादन का सवाल है, हम आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी यात्रा के निर्णायक और महत्वपूर्ण चरण में हैं। आजादी के बाद पहले तो हम मुख्यतः आयात पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन धीरे-धीरे हम सत्तर, अस्सी और नब्बे के दशकों में लाइसेंस प्राप्त उत्पादन की ओर बढ़ने लगे थे और अब अपने देश में ही डिजाइन, विकास और विनिर्माण करने की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, भारी इंजीनियरिंग इत्यादि जैसे अन्य क्षेत्रों की भांति ही मुझे उम्मीद है कि

देश में ही रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार लागू किए हैं। इनमें लाइसेंसिंग एवं एफडीआई नीति का उदारीकरण, ऑफसेट संबंधी दिशा-निर्देशों को सुव्यवस्थित करना, निर्यात नियंत्रण प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाना और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को समान अवसर देने से संबंधित मसलों को सुलझाना शामिल हैं।

निरंतर नीतिगत पहलों, कुशल प्रशासनिक प्रक्रिया और आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता की बदौलत भारतीय रक्षा उद्योग बेहतर प्रदर्शन करने लगेगा और इसके साथ ही हम निकट भविष्य में देश में ही प्रमुख रक्षा उपकरणों एवं प्लेटफॉर्मों की डिजाइनिंग, विकास और विनिर्माण शुरू होने के साक्षी बन सकते हैं। सुधारों की प्रक्रिया के साथ-साथ बिजनेस में आसानी या सुगमता सुनिश्चित करना भी एक सतत प्रक्रिया है और इसके साथ ही सरकार एवं उद्योग जगत को आपस में मिलकर एक ऐसा परितंत्र या सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जो इस क्षेत्र के विकास एवं स्थिरता के लिए आवश्यक है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के हमारे दीर्घकालिक हित में होगा। ■

(लेखक केंद्रीय रक्षा, वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री हैं।)

भारत का बदलता परिवहन परिदृश्य

| नितिन गडकरी |

किसी भी देश की प्रगति का व्यक्तियों की आवाजाही और माल की ढुलाई से संबंधित उसकी दक्षता से गहरा संबंध है। अच्छी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध संसाधनों, उत्पादन केन्द्रों और बाजार के बीच अनिवार्य संपर्क उपलब्ध कराते हुए आर्थिक वृद्धि में सहायता प्रदान करती है। यह देश के एकदम दूरदराज के क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति तक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए संतुलित क्षेत्रीय प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कारक भी है।

दुनिया के सबसे विशाल परिवहन नेटवर्क्स में से एक होने के बावजूद, भारत का परिवहन नेटवर्क लंबे अर्से से यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई के क्षेत्र में बहुत धीमी रफ्तार और अकुशलता से ग्रसित रहा। इस क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां रहीं। दूरदराज के क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों पर परिवहन नेटवर्क की पर्याप्त पहुंच का अभाव रहा। राजमार्ग संकरे, भीड़भाड़ वाले और खराब रख-रखाव वाले रहे, जिनकी वजह से यातायात की गति धीमी रहती थी, बहुमूल्य समय की हानि होती थी और प्रदूषण का भारी दबाव रहता था। इनकी वजह से आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और हर साल लगभग 1.5 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ती हैं। बहुत अधिक मात्रा में माल ढुलाई सड़क मार्ग के जरिये होती है, हालांकि यह साबित हो चुका है कि यह माल ढुलाई का सबसे महंगा साधन हैं और इससे प्रदूषण भी ज्यादा फैलता है। रेल परिवहन, सड़क परिवहन की तुलना में ज्यादा किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन है, लेकिन उसका नेटवर्क धीमा और अपर्याप्त है, जबकि जल मार्ग, जो परिवहन के तीनों साधनों में से सबसे किफायती और पर्यावरण के अनुकूल साधन है, बड़े पैमाने पर अल्प विकसित है। इस घाटे वाले मॉडल मिक्स के परिणामस्वरूप लॉजिस्टिक्स की लागत बहुत अधिक है, जिसकी वजह से हमारी वस्तुएं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैर प्रतिस्पर्धी बन जाती है।

हालांकि पिछले तीन-चार वर्षों से इस स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ है। सरकार ने देश में ऐसी विश्वस्तरीय परिवहन अवसंरचना का निर्माण करने को प्रमुख रूप से प्राथमिकता दी है, जो किफायती हो, सभी को आसानी से सुलभ हो सके, सुरक्षित हो और ज्यादा प्रदूषण फैलाने का कारण भी न बने और जहां तक हो सके अधिक से अधिक स्वदेशी सामग्री पर निर्भर हो। इसमें विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए उपलब्ध मौजूदा ढांचे को मजबूती प्रदान करना, नई बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना और इस कार्य में सहायक विधायी फ्रेमवर्क को आधुनिक बनाना शामिल है। इसमें निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी तथा ऐसी साझेदारी के लिए समर्थ बनाने वाले वातावरण का निर्माण करना और उसे प्रोत्साहन देना भी शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्ग देश के सड़क नेटवर्क का महज दो प्रतिशत अंश है, लेकिन वह यातायात के 40 प्रतिशत भार का वहन करता है। सरकार राजमार्गों की लंबाई और गुणवत्ता, दोनों के संदर्भ में इस बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है। वर्ष 2014 में 96,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग से शुरुआत करते हुए अब हमारे पास 1.5 लाख किलोमीटर राजमार्ग हैं और जल्द ही इनके 2 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। आगामी भारतमाला कार्यक्रम सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क सड़कों को जोड़ेगा, आर्थिक गलियारों, अन्तर-गलियारों और फीडर रूट्स का विकास करेगा, राष्ट्रीय गलियारों के सम्पर्क में सुधार लाएगा, तटीय और बंदरगाह सम्पर्क सड़कों और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज का निर्माण करेगा। इसका आशय है कि देश के समस्त क्षेत्रों की राष्ट्रीय राजमार्गों तक सुगम पहुंच होगी।

सड़क सम्पर्क का निर्माण करने के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र, नक्सल प्रभवित क्षेत्र, पिछड़े और आंतरिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। असम में ढोला सादिया सेतु जैसे पुल और जम्मू कश्मीर की चेनानी नाशरी सुरंग जैसी अत्याधुनिक सुरंगें, दुर्गम स्थानों की दूरियों को कम कर रहे हैं और दूरदराज के इलाकों तक पहुंच को ज्यादा सुगम बना रहे हैं। वडोदरा-मुम्बई,बेंगलूरू-चेन्नई और दिल्ली-मेरठ मार्ग जैसे यातायात के अधिक दबाव वाले गलियारे विश्वस्तरीय, एक्सेस कन्ट्रोल्ड एक्सप्रेसवेज की इंतजार में हैं, जबकि चार धाम और बौध सर्किट जैसे धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक

यात्रा त्वरित और ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगी।

राजमार्गों के किलोमीटर बढ़ाने के अलावा, हम उन्हें यातायात के लिए सुरक्षित बनाने के लिए भी संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए, एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें सड़कों के डिजाइन में सुरक्षा की विशेषताएं शामिल करना, दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों को दुरुस्त करना, सड़कों पर उचित संकेतक, ज्यादा प्रभावी कानून, वाहनों से संबंधित सुरक्षा के बेहतर मानक, चालकों का प्रशिक्षण, बेहतर ट्रामा केयर और जनता में जागरूकता बढ़ाना शामिल हैं। सेतु भारतम कार्यक्रम के अंतर्गत सभी रेलवे फाटकों को ओवर ब्रिज या अंडर पास से बदला गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी पुलों पर ढांचागत रेटिंग सहित एक इन्वेन्ट्री तैयार की जा रही है, ताकि उनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य समय पर किया जा सके।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया गया है और राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना है। विधेयक में सख्त जुर्माना, वाहनों की उपयुक्तता के प्रमाणीकरण और वाहन चालकों को लाइसेंस देने जैसे विषयों को कम्प्यूटर द्वारा पारदर्शी बनाना, मानव हस्तक्षेप न्यूनतम करना, कानूनी प्रावधानों और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का समावेश किया गया है।

प्रदूषण की समस्या को कम करने के मुद्दे पर भी विचार किया गया है। इसके तहत पुराने वाहनों को हटाना, 01 अप्रैल, 2020 से बीएस-6 उत्सर्जन नियमों को अपनाना, स्थानीय आबादी के सहयोग से राजमार्गो पर वृक्षारोपण तथा इलेक्ट्रनिक टोल कलेक्शन प्रक्रिया को लागू करना शामिल है, ताकि टोल प्लाजा के ऊपर वाहनों को कम समय तक इंतजार करना पड़े। इथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-डीजल, मीथेनॉल और बिजली के इस्तेमाल जैसे वैकल्पिक ईंधनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रायोगिक स्तर पर इन वैकल्पिक ईंधनों को कुछ शहरों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

सस्ते और हरित जल यातायात की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। भारत की 7500 किलोमीटर लम्बी तटरेखा और 14 हजार से अधिक लम्बे जलमार्गों का सागरमाला कार्यक्रम के जरिये क्षमता का आकलन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। सागरमाला के तहत बंदरगाहों के विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों के विकास के जरिये बंदरगाहों के आसपास उद्योग लगाने का विचार है। इस विचार के तहत बंदरगाह संरचना का आधुनिकीकरण किया जाएगा और सड़क, रेल तथा जलमार्गों के जरिये अंदरूनी हिस्सों को बंदरगाहों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही तटीय समुदायों का विकास किया जाएगा। उम्मीद की जाती है कि 35000- 40000 करोड़ रुपये की वार्षिक लॉजिस्टिक बचत के अलावा निर्यात लगभग 110 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगा तथा एक करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे। अगले 10 वर्षों के दौरान सागरमाला द्वारा घरेलू जलमार्गों की हिस्सेदारी दुगनी हो जाएगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त कई जलमार्गों पर काम चल रहा है। इनमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की नौवहन क्षमता का विकास किया जाएगा। गंगा नदी पर विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जलमार्ग विकास परियोजना का उद्देश्य हल्दिया से इलाहाबाद तक के क्षेत्र को विकसित करना है, ताकि वहां 1500-2000 टन जहाजों का नौवहन हो सके। वाराणसी, साहेबगंज और हल्दिया में बहु-स्तरीय टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। यहां अन्य आवश्यक संरचना का भी तेजी से विकास किया जा रहा है। इसके विकास से देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में माल का आवागमन होने लगेगा, जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी। अगले तीन सालों में 37 अन्य जलमार्गों को विकसित किया जाएगा।

राजमार्ग और जलमार्ग क्षेत्रों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा एकीकृत यातायात प्रणाली का विकास किया जा रहा है, जो इष्टतम मोडल और निर्बाध अंतर-मोडल सम्पर्कता पर आधारित है। इस संबंध में लॉजिस्टिक एफिशियेन्सी इनहांसमेंट प्रोग्राम तैयार किया गया है, ताकि देश में माल यातायात की क्षमता में बढ़ोतरी हो। इसमें 50 आर्थिक गलियारों, फीडर रूटों का उन्नयन, 35 मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्कों का विकास शामिल है। इन पार्कों में भंडारण और गोदाम की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इनके अलावा विभिन्न यातायात माध्यमों के एकीकरण के लिए 10 अंतर-मोडल स्टेशनों का निर्माण भी किया जाएगा।

भारत में यातायात क्षेत्र बहुत तेजी से बदल रहा है और देश के विकास में वह बड़ी भूमिका निभाएगा। भारतीय परिदृश्य में यह क्रांति दृष्टिगोचर हो रही है। इसके प्रकाश में हम यह आशा करते हैं कि इससे न केवल देश का तेज विकास होगा, बल्कि अब तक वंचित रहे क्षेत्रों और लोगों तक विकास के लाभ पहुंचेंगे। ■

(लेखक केंद्रीय सड़क यातायात एवं राजमार्ग और नौवहन मंत्री हैं।)

शीर्ष पर भाजपा

| कैलाश विजयवर्गीय |

भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद पर भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्यों के विराजमान होने से हमारे लोकतंत्र की अद्भुत शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। भारतीय संसदीय परम्परा में यह पहला अवसर है कि चार शीर्ष पदों पर भाजपा के कार्यकर्ता शोभा बढ़ा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिली विजय के बाद श्री नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। देश ने संसद में 30 साल किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया था। इस ऐतिहासिक विजय के बाद भाजपा का विजय रथ लगातार अग्रसर हो रहा है। आज 13 राज्यों में भाजपा की सरकार हैं और पांच राज्यों में गठबंधन सरकारें जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। लोकसभा में पहली बार ही भाजपा की माननीय सुमित्रा ताई अध्यक्ष बनीं। राजग के अन्य घटक दलों के सदस्य पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं पर यह पहली बार हुआ कि भाजपा की किसी साधारण सदस्य को यह पद मिला। भाजपा के माननीय रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति बने। बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे कोविंद जी का देश का राष्ट्रपति बनना कोई साधारण घटना नहीं है। दलित परिवार के कोविंद जी ने कहा भी कि ऐसा भाजपा में ही संभव था कि किसी गरीब परिवार को व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। अब 11 अगस्त को देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर भाजपा के पूर्व अध्यक्ष एम. वेकैंया नायडू शपथ लेंगे। किसान परिवार में जन्मे माननीय नायडू दक्षिण भारत से सातवें उपराष्ट्रपति हैं। हाजिर जवाबी नायडू जी अब उच्च सदन के सभापति होंगे। संसद में विपक्षी हमलों की धार को भौंथरा करने वाले नायडू ने उपराष्ट्रपति बनने से ही पहले कहा था कि वह निर्भय और निष्पक्ष होकर सदन का कामकाज संचालित करने की ईमानदार कोशिश करेंगे। सदन के कामकाज के नियमों और संकल्पों के अनुसार काम करने और सभी सदस्यों के सहयोग से सदन की मर्यादा को बनाए रखने का उन्होंने संदेश दिया है।

भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए यह गौरव की बात है कि उनके बीच काम करने वाले नेता आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। खासतौर पर यह भी महत्वपूर्ण हैं कि सभी साधारण घरों से शीर्ष पदों तक पहुंचे हैं। भाजपा के सिपाही के नाते और व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे इन सभी के साथ काम करने का अवसर मिला है। लोकसभा अध्यक्ष माननीया सुमित्रा ताई तो मेरे शहर इंदौर की शान हैं। आठ बार लोकसभा की सदस्य रहीं सुमित्रा ताई को सबको साथ लेकर चलने का अनुभव है। लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सभी दलों के नेताओं को साथ लेकर चलने की परम्परा को बहुत आगे बढ़ा दिया है। मोदी जी के बारे में तो देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि कैसे एक गरीब चाय वाले के परिवार में जन्मे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। गरीबों की भलाई में जुटे मोदी जी को देश के आर्थिक उत्थान में इस वर्ग का भरपूर समर्थन और प्यार मिला है। गरीबों के समर्थन के कारण ही हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लंबे समय से जात-पात की राजनीति करने वाले दलों को हाशिये पर पहुंचा दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी मोदी सरकार के उल्लेखनीय कार्यों के कारण भाजपा की सरकारें बनी। अब देश में भाजपायुक्त नारे का संकल्प पूरा हो रहा है। कांग्रेस मुक्त होते भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि शीर्ष चार पदों पर कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं है। यहां यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि उच्च सदन में भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय मध्य प्रदेश से उपचुनाव में जीती संपतिया उईके को मिला है। राज्यसभा में अगले साल भाजपा की ताकत और बढ़ जाएगी। भाजपा के विजय रथ के आगे बढ़ने के कारण अगले साल तक राज्यसभा में राजग को बहुमत मिल जाएगा। विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दलों को 11 करोड़ कार्यकर्ताओं की बदौलत उच्च सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनने का अवसर मिलेगा। भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह भी जल्दी ही राज्य सभा में दिखाई देंगे। मोदी और शाह की जोड़ी ने देश की राजनीति की दिशा और दशा पूरी तरह बदल दी है। भाजपा अध्यक्ष के हाल में विभिन्न राज्यों में दौरे के दौरान मिले जन समर्थन से दिखाई दे रहा है कि शीघ्र ही पूरे देश में भाजपा का परचम फहराने वाला है।

भाजपा में साधारण कार्यकर्ता से आगे बढ़े नायडू जी गंभीर बात को इस तरह कहते हैं कि बात सही तरीके से पहुंच जाती है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें उनकी मांग पर ही ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनसे जब इस पद पर उनकी दावेदारी के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि उषापति बनकर ही खुश हूं। सरकार या पार्टी की गंभीर बैठकों में भी उनकी हाजिर जवाबी की प्रशंसा होती रही है। दक्षिण भारतीय होने के बावजूद नायडू जी हिन्दी में अलंकारिक भाषा का प्रयोग करके वाकचातुर्यता में कोई मुकाबला नहीं था। हिन्दी के प्रबल समर्थक नायडू जी संसद में हर विषय पर प्रभावी राय रखते हैं। मोदी सरकार में शहरी विकास मंत्रालय मिलने पर भी उन्होंने कहा कि गांव से पलायन हो गया है। अटल सरकार में उन्होंने जिस मजबूती से गांवों में सड़क बनाने का काम किया और वो भी कई मंत्रियों के विरोध के बावजूद, वह उल्लेखनीय है। मोदी जी ने इसी आधार पर उनको देश के शहरों की सूरत बदलने का काम सौंपा, जो उन्होंने बखूबी निभाया। एक किसान परिवार में जन्म लेने वाले वेंकैया जी ने उपराष्ट्रपति बनने पर अभिभूत होकर कहा कि एक आम आदमी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है, उनकी जड़ें एक सामान्य किसान परिवार से जुड़ी हुई हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में नायडू जी को मिले मत भी बतातें है कि राजग का कुनबा बढ़ने वाला है। राजग के अलावा उन्हें विपक्षी दलों के सांसदों का भी समर्थन मिला है। राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के वोट कम हुए हैं। नायडूजी को मिला समर्थन बताता है कि विपक्ष को भी अपने नए सभापति में पूरा भरोसा है। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं।)

कम्युनिस्टों की तालिबानी मानसिकता

संजय द्विवेदी

केरल में आए दिन हो रही राजनीतिक हत्याओं से एक सवाल उठना लाजिमी है कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में क्या असहमति की आवाजें खामोश कर दी जाएगीं? एक तरफ वामपंथी बौद्धिक गिरोह देश में असहिष्णुता की बहस चलाकर मोदी सरकार को घेरने का असफल प्रयास कर रहा है। वहीं, दूसरी ओर उनके समान विचारधर्मी दल की केरल की राज्य सरकार के संरक्षण में असहमति की आवाज उठाने वालों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अपने विचारों, के प्रसार की सबको आजादी देता है। भारत के विभिन्न राज्यों में भाषाई मतभेद, जातीय मतभेद और राजनीतिक मतभेद हमेशा से रहे हैं। सरकार की नीतियों का विरोध भी होता रहा है। उसके तरीके जनांदोलन, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी,बाजार बंद कराना जैसे विविध प्रकल्प राजनीतिक दल करते रहे हैं। अभी हाल में ही भारत में हुए राजनीतिक परिवर्तन के तहत केंद्र सहित कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनता के बहुमत से सत्ता में आई हैं। जब यह सत्ता परिवर्तन हो रहा था तो हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी इसे पचा नहीं पा रहे थे और वे छोटी सी बात को तिल का ताड़ बनाने का काम कर रहे थे। उनकी इस मुहिम में मीडिया का एक बड़ा वर्ग शामिल था। हम देखते हैं कि जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां विरोधी दलों के साथ एक लोकतांत्रिक व्यवहार कायम है। लेकिन केरल में जिस तरह से राजनीतिक विरोधियों को कुचलने और समाप्त कर डालने की हद तक जाकर कुचक्र रचे जा रहे हैं, वह आश्चर्य में डालते हैं। केरल में पिछले 13 महीने में दो दर्जन से अधिक स्वयंसेवकों की हत्याएं हो चुकी हैं। यह आंकड़ा पुलिस ने बताया है। जबकि चश्मदीद लोग इससे भी अधिक बर्बरता की कहानी बताते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने केरल में हो रही आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्याओं का आरोप सीपीएम पर लगाया है। उनका कहना है कि जिस-जिस क्षेत्र में सरकार की नीतियों का हमारे कार्यकर्ता लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करते हैं, उन्हें या तो पुलिस थानों में अकारण बंद कर दिया जाता है और बाद में झूठे मुकदमे लादकर अपराधी घोषित कर दिया जाता है। कई जगहों पर स्वयंसेवकों को घरों से खींचकर गोलियों से उड़ाया जा रहा है। यह तांडव राज्य सरकार के संरक्षण में वामपंथी कार्यकर्ता कर रहे हैं। चूंकि शासन-सरकार का वामपंथियों को संरक्षण प्राप्त है, इसलिए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। केरल की इन रक्तरंजित घटनाओं को लेकर पिछले दिनों लोकसभा में भी जमकर हंगामा हुआ, जबकि केंद्र सरकार ने केरल के मुख्यमंत्री से इस संबंध में जवाब तलब किया है। परंतु आरएसएस का मानना है कि राज्य सरकार के इशारे पर अफसर सही जानकारी केंद्र को नहीं भेजते हैं।

केरल में जो घटनाएं हो रही हैं वे कम्युनिस्टों की तालिबानी मानसिकता का परिचायक हैं ये पूरी तरह लक्षित और सुनियोजित हमले हैं। इन हमलों में मुख्य रूप से दलित स्वयंसेवकों को निशाना बनाया गया है। केरल में आरएसएस के बढ़ते प्रभाव और वामपंथियों की खिसकती जमीन के चलते वामपंथी हिंसक हो रहे हैं। वे आरएसएस सहित दूसरे विरोधियों पर भी हिंसक हमले कर रहे हैं, पर न जाने किन राजनीतिक कारणों से कांग्रेस वहां खामोश है, जबकि उनके अपने अनेक कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हुए हैं और कई की जानें भी गयी हैं। एक तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का आलाप और दूसरी तरफ विरोधी विचारों को खामोश कर देने की खूनी जंग भारतीय वामपंथियों के असली चेहरे को उजागर करती है। यह बात बताती है कि कैसे विपक्ष में रहने पर उनके सुर अलग और सत्ता में होने पर उनका आचरण क्या होता है। निर्दोष संघ कार्यकर्ता तो किसी राजनीतिक दल का हिस्सा भी नहीं हैं, किंतु फिर भी उनके साथ यह आचरण बताता है कि वामपंथी किस तरह हिंदू विरोधी रूख अख्तियार किए हुए हैं। राजनीति के क्षेत्र में केरल एक ऐसा उदाहरण है जिसकी बर्बरता की मिसाल मिलना कठिन है। एक सुशिक्षित राज्य होने के बाद भी वहां के मुख्य और सत्तारूढ़ दल का आचरण आश्चर्य चकित करता है। पिछले दिनों केरल की घटनाओं की आंच तो दिल्ली तक पहुंची है और लोकसभा में इसे लेकर हंगामा हुआ है। भाजपा ने केरल की घटनाओं पर चिंता जताते हुए एनआईए या सीबीआई जांच की मांग की है।

हमें यह देखना होगा कि हम ऐसी घटनाओं पर किस तरह चयनित दृष्टिकोण अपना रहे हैं। अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमलों पर हमारी पीड़ा छलक पड़ती है, किंतु जब केरल में किस दलित हिंदू युवक के साथ यही घटना होती है हमारी राजनीति और मीडिया, खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे बर्बर आचरण पर किसी को कोई दर्द नहीं है। हमें देखना होगा कि आखिर हम कैसा लोकतंत्र बना रहे हैं। हम किस तरह विरोधी विचारों को नष्ट कर देना चाहते हैं। आखिर इससे हमें क्या हासिल हो रहा है। क्या राजनीति एक मनुष्य की जान से बड़ी है। क्या संघ के लोगों को केरल में काम करने का अधिकार नहीं है। आरएसएस नेता दत्तात्रेय होसवाले ने अपनी प्रेस कांफ्रेस में जो वीडियो जारी किए हैं वह बताते हैं कि वामपंथी किस दुष्टता और अमानवीयता पर आमादा हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। किस तरह वे गांवों में जूलूस निकालकर संघ के स्वयंसेवकों को कुत्ते की औलाद कहकर नारे बाजी कर रहे हैं। वे धमकी भरी भाषा में नारे लगा रहे हैं कि अगर संघ में रहना है तो अपनी मां से कहो वे तुम्हें भूल जाएं। आखिर यह किस राजनीतिक दल की सोच और भाषा है? आखिर क्या वामपंथी का वैचारिक और सांगठनिक आधार दरक गया है जो उन्हें भारतीय लोकतंत्र में रहते हुए इस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या यह उनका नैसर्गिक चरित्र है। कारण जो भी हों लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाली हर आवाज को आज केरल में आरएसएस के साथ खड़े होकर इन निर्मम हत्याओं की निंदा करनी चाहिए। ■

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक हैं)

वेंकैया नायडू बने 13वें उप राष्ट्रपति

भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री वेंकैया नायडू 5 अगस्त को देश के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 785 में से 771 सांसदों ने वोट डाला। यानी 98.2% मतदान हुआ। उपराष्ट्रपति चुनाव में यह अब तक का सबसे ज्यादा मतदान रहा। श्री नायडू को अपने प्रतिद्वंद्वी श्री गोपालकृष्ण गांधी से दोगुने से भी ज्यादा वोट मिले। श्री नायडू को 516 सांसदों के वोट मिले, जबकि श्री गांधी को 244 वोट मिले। यह 25 साल में सबसे बड़े अंतर की भी जीत है। इससे पहले 1992 में श्री के. आर. नारायणन को 701 में से 700 वोट मिले थे। श्री नायडू 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। हालांकि, इस पद पर बैठने वाले वह 13वें व्यक्ति होंगे। डॉ. श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन और श्री हामिद अंसारी दो-दो बार इस पद पर रह चुके हैं। निवर्तमान उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। श्री वेंकैया नायडू 11 अगस्त को शपथ लेंगे। भाजपा के लिए यह गर्व की बात है कि एक साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जैसे देश के शीर्ष चार पदों पर भाजपा कार्यकर्ता आसीन हैं।

एक किसान के बेटे की उप-राष्ट्रपति पद के लिए हुई जीत हर उस किसान की जीत है जो देश के विकास में योगदान कर रहा है। श्री नायडू की व्यापक जानकारी और विशाल अनुभव उप-राष्ट्रपति पद एवं राज्यसभा के लिए एक "बड़ी पूंजी" होगी।

—अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

श्री वेंकैया नायडू उप राष्ट्रपति के रूप में पूरी लगन और समर्पण के भाव से राष्ट्र की सेवा करेंगे और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे। वे समर्पित और कठिन परिश्रमी उप राष्ट्रपति साबित होंगे और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे।

—नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

उप राष्ट्रपति चुने जाने के बाद श्री वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने साथ ही समर्थन देने वाले सभी नेताओं का भी आभार जताया। उप राष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी और कांग्रेस अध्यक्ष श्री सोनिया गांधी ने भी श्री वेंकैया नायडू को बधाई दी।

चुनाव नतीजों के बाद श्री वेंकैया नायडू ने कहा- किसान पृष्ठभूमि से आने की वजह से मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी कि मैं यहां पहुंच सकूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय राजनीति में कृषि को उपयुक्त आवाज नहीं मिल पाई है। श्री नायडू ने कहा- 'मैं कृतार्थ हूं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी पार्टी नेताओं का समर्थन देने के लिए आभारी हूं। मैं उप राष्ट्रपति संस्था का उपयोग राष्ट्रपति के हाथ मजबूत बनाने के लिए करूंगा और ऊपरी सदन की मर्यादा को कायम रखूंगा। ■

राज्यसभा में बिल अटका कर कांग्रेस ने देश के पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया है: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 3 अगस्त को तिलयार कन्वेंशन सेंटर, रोहतक (हरियाणा) में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए राज्य सभा में लाये गए बिल में अड़ंगा लगाने के लिए कांग्रेस पर जम कर प्रहार किया।

श्री शाह ने कहा कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता दिलाने वाले बिल को राज्य सभा में अटका कर कांग्रेस ने देश के पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया है। ओबीसी कमीशन को मान्यता दिए जाने की मांग 1955 से लगातार हो रही थी, लेकिन आज तक किसी सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह प्रयास किया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिले और इसके लिए हम एक बिल और संविधान संशोधन विधेयक लेकर आये। उन्होंने कहा कि लोकसभा में यह बिल पारित भी हो गया, लेकिन राज्य सभा में कांग्रेस ने इस बिल में एक ऐसा अमेंडमेंट रखा कि यदि इस अमेंडमेंट को अपनाते हैं तो पूरा विधेयक ही कानूनी पचड़े में पड़ जाएगा। इसलिए कांग्रेस के इस अमेंडमेंट को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस अमेंडमेंट पर चर्चा प्रवर समिति में पहले ही हो गई थी और प्रवर समिति के सदस्यों ने बताया था कि इस अमेंडमेंट को अपनाने से पूरा विधेयक ही कानूनी पचड़े में पड़ जाएगा और यह बिल पास नहीं हो पायेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यह बात सदन में रिकॉर्ड पर भी रखा, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझकर अमेंडमेंट करने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम यह हुआ कि देश का पिछड़ा वर्ग जिस सम्मान के लिए 1955 से तरस रहा था, उसे और कुछ समय तक इस सम्मान से महरूम होने के लिए विवश हो जाना पड़ा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सभा में कांग्रेस द्वारा ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने वाले विधेयक में अड़ंगा लगाने की घटना के कारण कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता उजागर हो गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात करने से पिछड़े वर्ग का कल्याण नहीं होगा, बल्कि इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आप पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कोई ठोस कदम उठा नहीं पाए, लेकिन अगर कोई और यह कदम उठा रहा है तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए था और ऐसी चीजें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मुझे दुःख है कि कांग्रेस पार्टी ने उच्च सदन में इस विधेयक को पास नहीं होने दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का पिछड़े वर्ग के कल्याण एवं उनके सम्मान के लिए जो कमिटमेंट है, उसमें कांग्रेस पार्टी जितने भी रोड़े अटकाए, यह बिल संसद के दोनों सदनों से पास होकर क़ानून बन कर रहेगा। अब इसको कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो पिछड़ा वर्ग के विकास में रोड़ा अटकाने की जो नीति है, पूरा देश उसको जान गया है। श्री शाह ने कहा, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने सत्ता को पाने के लिए समाज के सभी वर्गों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया परंतु सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को आम जनता तक पहुंचाने के लिए कभी गंभीर एवं प्रभावी उपायों को लागू नहीं किया। यही कारण है कि आज़ादी के 70 साल बाद देश के सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को न्यायपूर्ण संस्था देने का काम जिस संविधान संशोधन के माध्यम से श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार करने जा रही थी, उसको रोकने का काम कांग्रेस ने राज्य सभा में किया।

श्री शाह ने कहा कि भाजपा हमेशा से सामाजिक समरसता के सिद्धांत पर चलती रही है। हमारे लिए हमारे लिए सामाजिक समरसता का अर्थ न्यायिक, आर्थिक और शैक्षिक - सभी तरीकों से देश के सभी वर्ग के लोगों को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि इसी लक्ष्य के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देकर वंचित वर्गों को अवसरों की सुरक्षा देकर न्यायपूर्ण शासन की कल्पना की गयी थी, जिसको धोखा देकर कांग्रेस ने अटका दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इस संविधान संशोधन के लिए कमिटेड है, आने वाले दिनों में हम इस संविधान संशोधन को दोनों सदनों में फिर से पास कराने का प्रयास जरूर करेंगे। ■

राज्य सभा में कांग्रेस द्वारा ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने वाले विधेयक में अड़ंगा लगाने की घटना के कारण कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग विरोधी मानसिकता उजागर हो गई है। यही नहीं, सिर्फ पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात करने से पिछड़े वर्ग का कल्याण नहीं होगा, बल्कि इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

रा.स्व.संघ स्वयंसेवक राजेश की हत्या

प्रतिद्वंद्वी दल के सदस्यों को खत्म करने के लिए माकपा अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा के कार्यालयों और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। इससे भाजपा, रा.स्व.संघ और अन्य को दबाया नहीं जा सकता। इससे कार्यकर्ताओं का समर्पण और बढ़ेगा। श्री राजेश का त्याग हर कार्यकर्ता को प्रेरित करेगा।

केरल में 29 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 34 वर्षीय कार्यवाह श्री राजेश पर हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। उनका बायां हाथ काट दिया गया और उनके शरीर पर 70-80 घाव थे। केरल भाजपा के अध्यक्ष श्री कुम्मनम राजशेखरन ने कहा कि हमले के पीछे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ है।

इस घटना के विरोध में भाजपा ने राज्यव्यापी हड़ताल आहूत की थी, जो पूरी तरह सफल रही। सरकारी और निजी बसें सड़कों से नदारद रहीं, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे।

हत्या को बर्बर करार देते हुए श्री राजशेखरन ने कहा कि यह रा.स्व.संघ और भाजपा को खत्म करने के लिए की जा रही विनाश की राजनीति है। उन्होंने कहा कि भाजपा मामले को प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृहमंत्री और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष उठाएगी। ■

भाजपा ने संसद में उठाया केरल में हुई हत्याओं का मुद्दा

भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने 2 अगस्त को लोकसभा में केरल में राजनीतिक कारणों से हुई हत्याओं का मुद्दा उठाया और राज्य में माकपा नेतृत्व वाले वाम मोर्चा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री प्रहलाद जोशी ने शून्य काल के दौरान कहा, 'केरल में वाम मोर्चा के 17 महीनों के कार्यकाल में 17 लोग मारे जा चुके हैं।'

श्री जोशी ने कहा, "कांग्रेस कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, लेकिन वे उनके साथ दिल्ली में सांठगांठ कर रहे हैं और केरल में लड़ रहे है।" भाजपा सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने राजनीतिक हिंसा के कथित पीड़ितों नामों की सूची पढ़ी। उन्होंने कहा, 'ये उन लोगों के नाम हैं, जो केरल में राजनीति से प्रेरित हत्याओं के शिकार हुए। असहिष्णुता और लोकतंत्र पर भाषण देने वाले लोकतंत्र में वैकल्पिक विचारधाराओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते।" उन्होंने कहा, "इस्लामिक स्टेट (आईएस) में शामिल होने वाले भी मुख्य रूप से इसी राज्य से आते हैं।" उन्होंने कहा, "जब भाजपा कार्यकर्ता मारे जाते हैं, तब हम आवाज उठाते हैं। अन्य तो आवाज भी नहीं उठाते। राजनीति हत्या करने का लाइसेंस नहीं देती।"

लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा अस्वीकार्य : राजनाथ सिंह

केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा अस्वीकार्य है। उन्होंने इस मुद्दे पर केरल के मुख्यमंत्री मंत्री श्री पिनराई विजयन से भी बात की।

श्री राजनाथ सिंह ने 30 जुलाई को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी संदेश में कहा कि केरल में राजनीतिक हिंसा की हालिया घटनाओं पर आज केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन से बात की। मैंने केरल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा अस्वीकार्य है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मुझे उम्मीद है कि केरल में राजनीतिक हिंसा रुकेगी और हमलावरों को शीघ्र न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाएगा।

हिंसा से संघ व भाजपा को दबाना नामुमकिनः अरुण जेटली

केरल में राजनीतिक हत्याओं को लेकर केंद्रीय वित्त और रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली ने राज्य की माकपा सरकार पर तगड़ा हमला बोला। श्री जेटली ने कहा कि संघ और भाजपा को हिंसा के जरिए दबाना मुमकिन नहीं है। प्रतिद्वंद्वी दल के सदस्यों को खत्म करने के लिए माकपा अपने कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रही है। रक्षा मंत्री ने राज्य के हालात को लेकर उन लोगों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, जो देश के अन्य हिस्सों में हाने वाली इसी तरह की घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों रक्षामंत्री हिंसा में मारे गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता श्री राजेश एडावाकोडे के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी।

गौरतलब है कि केरल में 29 जुलाई को संघ के कार्यकर्ता श्री राजेश की हत्या कर दी गई थी और भाजपा एवं संघ कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले किए गए थे। केन्द्र सरकार ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया और केंद्रीय मंत्री श्री जेटली को वहां के हालात का जायजा लेने भेजा। पीड़ित परिजन और भाजपा व संघ के कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद श्री जेटली ने कहा कि केरल की एलडीएफ सरकार ने हिंसा रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। श्री जेटली ने कहा कि केरल को कुदरत का तोहफा मिला है, लेकिन किसी सरकार के लिए यह चुनौती होगी कि इसे देश में सबसे ज्यादा समृद्ध कैसे बनाया जाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि नीति भटक जाती है और पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने और हिंसा का माहौल बनाने के लिए किया जाए तो सत्ताधारी पार्टी को गंभीरता से आत्म-मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यालयों और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। इससे भाजपा, आरएसएस और अन्य को दबाया नहीं जा सकता। इससे कार्यकर्ताओं का समर्पण और बढ़ेगा। भाजपा नेता ने कहा कि देश के अन्य हिस्सों में होने वाली ऐसी ही घटनाओं के खिलाफ नियमित तौर पर बोलने वाले लोग केरल में लगातार हो रही हिंसा पर पूरी तरह चुप हैं।

श्री जेटली ने श्री राजेश के घर जाकर उनके बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और बच्चों से मुलाकात की और उनका ढांढस बंधाया। श्री जेटली ने कहा कि कार्यकर्ता की जघन्य हत्या की गई और उसके शरीर पर 70-80 जख्म थे। उन्होंने कहा कि देश का दुश्मन भी ऐसा नहीं करता और एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि श्री राजेश का त्याग हर कार्यकर्ता को प्रेरित करेगा। अब उनके परिवार की देखरेख करना भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने एक अन्य रा.स्व.संघ के स्वयंसेवक श्री जयप्रकाश के परिजन से भी मुलाकात की। माकपा के हमले में श्री जयप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया था। श्री जेटली के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री कुम्मनम राजशेखरन भी थे। रा.स्व.संघ ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। ■

प्रधानमंत्री का पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को मार्मिक पत्र

प्रणब दा की सरलता, ऊंचे सिद्धांतों और असाधारण नेतृत्व ने हम सबको प्रेरित किया : नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिरी दिन 24 जुलाई को एक मार्मिक पत्र लिखा। प्रधानमंत्री के इस पत्र ने उनके दिल को छू लिया। यहां प्रस्तुत है पत्र के अंग्रेजी मूलपाठ का हिन्दी अनुवाद:

नई दिल्ली
24 जुलाई, 2017

प्रिय प्रणब दा,

अब जबकि आप अपनी एक नयी यात्रा के दौर की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं राष्ट्र को समर्पित आपके योगदान खासतौर पर पिछले पांच सालों में देश के राष्ट्रपति के रूप में किये गए आपके योगदान के लिए सराहना और कृतज्ञता का भाव व्यक्त करता हूं। आपकी सरलता, ऊंचे सिद्धांतों और असाधारण नेतृत्व ने हम सबको प्रेरित किया है।

तीन साल पहले मैं एक बाहरी व्यक्ति के तौर पर नई दिल्ली आया था। मेरे सामने विशाल और चुनौतीपूर्ण काम थे। इस दौर में आप हमेशा मेरे लिए एक पितातुल्य मार्गदर्शक रहे। आपकी बुद्धिमत्ता, आपके मार्गदर्शन और व्यक्तिगत स्नेह ने मुझे आत्मविश्वास और शक्ति दी है।

यह सर्वविदित है कि आप ज्ञान के एक भंडार हैं। नीति से राजनीति, आर्थिक मामले से विदेशी मामले, सुरक्षा के विषयों से राष्ट्रीय और वैश्विक महत्त्व के विषयों सहित विभिन्न मामलों पर आपकी विद्वता से मैं हमेशा आश्चर्यचकित होता रहा हूं। आपके बौद्धिक कौशल ने निरन्तर मेरी सरकार और मेरी मदद की है।

आप मेरे लिए अत्यन्त स्नेही और ध्यान रखने वाले व्यक्ति रहे हैं। दिन भर चलने वाली बैठकों या प्रचार अभियान यात्रा के बाद आपका ऐसा एक फोन कॉल मुझमें ताजगी और ऊर्जा भर देने के लिए पर्याप्त होता था, जिसमें आप कहते थे, 'मैं आशा करता हूं कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं।'

प्रणब दा, हमारी राजनीतिक यात्राओं ने अलग-अलग दलों में आकार लिए। समय-समय पर हमारी विचारधाराएं भिन्न रही हैं। हमारे अनुभव भी अलग-अलग हैं। मेरा प्रशासनिक अनुभव मेरे राज्य से था, जबकि आपने दशकों तक राष्ट्रीय नीति और राजनीति को देखा है। इसके बावजूद, आपकी बौद्धिकता और बुद्धिमत्ता में ऐसी ताकत है कि हम तालमेल के साथ मिलकर काम करने में समर्थ थे।

अपनी राजनीतिक यात्रा और राष्ट्रपति काल के दौरान, आपने राष्ट्र की खुशहाली को अन्य सभी चीजों से ऊपर रखा। आपने उन पहलों और कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खोल दिए, जो नवीन खोजों और भारत के युवाओं की प्रतिभा के लिए महत्त्वपूर्ण थे।

आप नेताओं की उस पीढ़ी से हैं जिसके लिए राजनीति समाज की निःस्वार्थ सेवा का एक माध्यम है। भारत की जनता के लिए आप प्रेरणा का एक महान स्रोत हैं। भारत हमेशा आप पर गर्व करेगा कि आप एक ऐसे राष्ट्रपति रहे, जो एक विनम्र जनसेवक और असाधारण नेता भी हैं।

आपकी विरासत हमारा निरंतर मार्गदर्शन करेगी। हम आपके सबको साथ लेकर चलने वाले लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से निरंतर शक्ति प्राप्त करते रहेंगे, जिसे आपने अपने लम्बे और उत्कृष्ट सार्वजनिक जीवन में संजोया है। अब जबकि आप अपने जीवन के एक नये चरण में प्रवेश कर रहे हैं, आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं।

आपके समर्थन, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। मैं आपके उन अत्यंत प्यारे शब्दों के लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं, जो आपने कुछ दिन पूर्व संसद में विदाई कार्यक्रम में मेरे बारे में बोले थे। राष्ट्रपति जी, आपके प्रधानमंत्री के रूप में आपके साथ काम करना मेरे लिए एक सम्मान की बात रही है।

जय हिन्द!

आपका

(नरेन्द्र मोदी)

भारत की सामूहिक शक्ति की सफलता का उत्तम उदाहरण है जीएसटी: नरेंद्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान कहा कि जीएसटी के लागू हुए क़रीब एक महीना हुआ है और उसके फ़ायदे दिखने लगे हैं और मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है, जब कोई ग़रीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि जीएसटी के कारण एक ग़रीब की ज़रुरत की चीज़ों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीज़ें कैसे सस्ती हुई हैं।

उन्होंने कहा कि अगर नार्थ-ईस्ट, दूर-सुदूर पहाड़ों में, जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है; लेकिन अब जब मैं उसमें सीखने-समझने लगा, तो मुझे लगता है, पहले से ज़्यादा आसान हो गया काम। व्यापार और आसान हो गया और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी मैं देख रहा था कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर पर कैसे जीएसटी का प्रभाव पड़ा? कैसे अब ट्रकों की आवाजाही बढ़ी है! दूरी तय करने में समय कैसे कम हो रहा है ! हाईवे बाधा मुक्त हुए हैं। ट्रकों की गति बढ़ने के कारण प्रदूषण भी कम हुआ है। सामान भी बहुत जल्दी से पहुंच रहा है। ये सुविधा तो है ही, लेकिन साथ-साथ आर्थिक गति को भी इससे बल मिलता है।

उन्होंने कहा कि पहले अलग-अलग कर संरचना होने के कारण ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर का अधिकतम संसाधन पेपरवर्क मेन्टेन करने में लगता था और उसको हर राज्य के अन्दर अपने नये-नये वेयरहाउस बनाने पड़ते थे। जीएसटी-जिसे मैं गुड एंड सिंपल टैक्स कहता हूं, सचमुच में उसने हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव और बहुत ही कम समय में उत्पन्न किया है। जिस तेज़ी से स्मूथ ट्रांज़िशन हुआ है, जिस तेज़ी से माइग्रेशन हुआ है, नये पंजीकरण हुए हैं, इसने पूरे देश में एक नया विश्वास पैदा किया है।

श्री मोदी ने कहा कि कभी-न-कभी अर्थव्यवस्था के पंडित, प्रबंधन के पंडित, तकनीक के पंडित, भारत के जीएसटी के प्रयोग को विश्व के सामने एक मॉडल के रूप में शोध करके ज़रूर लिखेंगे। दुनिया की कई यूनिवर्सिटियों के लिए एक केस स्टडी बनेगा। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा परिवर्तन और इतने करोड़ों लोगों की भागीदारी के साथ इतने बड़े विशाल देश में उसको लागू करना और सफलतापूर्वक आगे बढ़ना, ये अपने-आप में सफलता की एक बहुत बड़ी ऊंचाई है। विश्व ज़रूर इस पर अध्ययन करेगा और जीएसटी लागू किया है, सभी राज्यों की उसमें भागीदारी है, सभी राज्यों की ज़िम्मेवारी भी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे निर्णय राज्यों ने और केंद्र ने मिलकर के सर्वसम्मति से किए हैं और उसी का परिणाम है कि हर सरकार की एक ही प्राथमिकता रही कि जीएसटी के कारण ग़रीब की थाली पर कोई बोझ न पड़े और जीएसटी एप्प पर आप भली-भांति जान सकते हैं कि जीएसटी के पहले जिस चीज़ का जितना दाम था, तो नई परिस्थिति में कितना दाम होगा, वो सारा आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध है। 'एक राष्ट्र-एक कर', कितना बड़ा सपना पूरा हुआ।

श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी के मसले को मैंने देखा है कि जिस प्रकार से तहसील से ले करके भारत सरकार तक बैठे हुए सरकार के अधिकारियों ने जो परिश्रम किया है, जिस समर्पण भाव से काम किया है, एक प्रकार से जो अनुकूल माहौल बना सरकार और व्यापारियों के बीच, सरकार और ग्राहकों के बीच, उसने विश्वास को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मैं इस कार्य से लगे हुए सभी मंत्रालयों को, सभी विभागों को, केंद्र और राज्य सरकार के सभी मुलाज़िमों को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

उन्होंने कहा कि जीएसटी भारत की सामूहिक शक्ति की सफलता का एक उत्तम उदाहरण है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और ये

सिर्फ कर सुधार नहीं है, एक नयी ईमानदारी की संस्कृति को बल प्रदान करने वाली अर्थव्यवस्था है। एक प्रकार से एक सामाजिक सुधार का भी अभियान है। मैं फिर एक बार सरलतापूर्वक इतने बड़े प्रयास को सफल बनाने के लिए कोटि-कोटि देशवासियों को कोटि-कोटि वंदन करता हूं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगस्त महीना क्रांति का महीना होता है। सहज रूप से ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं और उसका कारण है, 1 अगस्त, 1920 – 'असहयोग आन्दोलन' प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त, 1942 – 'भारत छोड़ो आन्दोलन' प्रारंभ हुआ, जिसे 'अगस्त क्रांति' के रूप में जाना जाता है और 15 अगस्त, 1947 - देश आज़ाद हुआ। एक प्रकार से अगस्त महीने में अनेक घटनायें आज़ादी की तवारीख़ के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं।

श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष हम 'भारत छोड़ो आन्दोलन' की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि 'भारत छोड़ो'-ये नारा डॉ. यूसुफ़ मेहर अली ने दिया था। हमारी नयी पीढ़ी को जानना चाहिए कि 9 अगस्त, 1942 को क्या हुआ था? 1857 से 1942 तक जो आज़ादी की ललक के साथ देशवासी जुड़ते रहे, जूझते रहे, झेलते रहे, इतिहास के पन्ने भव्य भारत के निर्माण के लिए हमारी प्रेरणा हैं। हमारे आज़ादी के वीरों ने त्याग, तपस्या, बलिदान दिए हैं, उससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'भारत छोड़ो आन्दोलन' भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। इसी आन्दोलन ने ब्रिटिश-राज से मुक्ति के लिये पूरे देश को संकल्पित कर दिया था। ये वो समय था, जब अंग्रेज़ी सत्ता के विरोध में भारतीय जनमानस हिंदुस्तान के हर कोने में, गांव हो, शहर हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, ग़रीब हो, अमीर हो, हर कोई कंधे-से-कंधा मिला करके 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का हिस्सा बन गया था।

श्री मोदी ने कहा कि 1947 में हम आज़ाद हुए। आज 2017 है। क़रीब 70 साल हो गए। सरकारें आईं-गईं। व्यवस्थायें बनीं, बदलीं, पनपीं, बढ़ीं। देश को समस्याओं से मुक्त कराने के लिये हर किसी ने अपने-अपने तरीक़े से प्रयास किए। देश में रोज़गार बढ़ाने के लिये, ग़रीबी हटाने के लिये, विकास करने के लिये प्रयास हुए। अपने-अपने तरीक़े से परिश्रम भी हुआ। सफलतायें भी मिलीं। अपेक्षायें भी जगीं। जैसे 1942 to 1947 संकल्प से सिद्धि के एक निर्णायक पांच वर्ष थे। मैं देख रहा हूं कि 2017 से 2022 - संकल्प से सिद्धि के और एक पांच साल का तबका हमारे सामने आया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस 2017 के 15 अगस्त को हम संकल्प पर्व के रूप में मनाएं और 2022 में आज़ादी के जब 75 साल होंगे, तब हम उस संकल्प को सिद्धि में परिणत करके ही रहेंगे। अगर सवा-सौ करोड़ देशवासी 9 अगस्त, क्रांति दिवस को याद करके, इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करे, व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में - मैं देश के लिए इतना करके रहूंगा, परिवार के रूप में ये करूंगा, समाज के रूप में ये करूंगा, गांव और शहर के रूप में ये करूंगा, सरकारी विभाग के रूप में ये करूंगा, सरकार के नाते ये करूंगा। करोड़ों-करोड़ों संकल्प हों। करोड़ों-करोड़ों संकल्प को परिपूर्ण करने के प्रयास हों। तो जैसे 1942 to 1947 पांच साल देश को आज़ादी के लिए निर्णायक बन गए, ये पांच साल 2017 से 2022 के, भारत के भविष्य के लिए भी निर्णायक बन सकते हैं और बनाने हैं।

श्री मोदी ने कहा कि पांच साल बाद देश की आज़ादी के 75 साल मनाएंगे। तब हम सब लोगों को दृढ़ संकल्प लेना है आज। 2017 हमारा संकल्प का वर्ष बनाना है। यही अगस्त मास संकल्प के साथ हमें जुड़ना है और हमें संकल्प करना है। गंदगी - भारत छोड़ो, ग़रीबी - भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार - भारत छोड़ो, आतंकवाद - भारत छोड़ो, जातिवाद - भारत छोड़ो, सम्प्रदायवाद - भारत छोड़ो। आज आवश्यकता 'करेंगे या मरेंगे' की नहीं, बल्कि नये भारत के संकल्प

15 अगस्त को हम संकल्प पर्व के रूप में मनाएं और 2022 में आज़ादी के जब 75 साल होंगे, तब हम उस संकल्प को सिद्धि में परिणत करके ही रहेंगे। अगर सवा-सौ करोड़ देशवासी 9 अगस्त, क्रांति दिवस को याद करके, इस 15 अगस्त को हर भारतवासी संकल्प करे, व्यक्ति के रूप में, नागरिक के रूप में - मैं देश के लिए इतना करके रहूंगा, परिवार के रूप में ये करूंगा, समाज के रूप में ये करूंगा, गांव और शहर के रूप में ये करूंगा, सरकारी विभाग के रूप में ये करूंगा, सरकार के नाते ये करूंगा।

के साथ जुड़ने की है, जुटने की है, जी-जान से सफलता पाने के लिये पुरुषार्थ करने की है। संकल्प को लेकर के जीना है, जूझना है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए, इस अगस्त महीने में 9 अगस्त से संकल्प से सिद्धि का एक महाभियान चलाएं। प्रत्येक भारतवासी, सामाजिक संस्थायें, स्थानीय निकाय की इकाइयां, स्कूल, कॉलेज, अलग-अलग संगठन - हर एक नए भारत के लिए कुछ-न-कुछ संकल्प लें। एक ऐसा संकल्प, जिसे अगले 5 वर्षों में हम सिद्ध करके दिखाएंगे। युवा संगठन, छात्र संगठन, NGO आदि सामूहिक चर्चा का आयोजन कर सकते हैं। नये-नये विचार उजागर कर सकते हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमें कहां पहुंचना है? एक व्यक्ति के नाते उसमें मेरा क्या योगदान हो सकता है? आइए, इस संकल्प के पर्व पर हम जुड़ें। ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

राज्यसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी

भारतीय जनता पार्टी के पास अब राज्यसभा में 58 सदस्य हैं, जो इसे संसद के ऊपरी सदन में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास 57 सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सांसद सम्पतिया उईके, जो ऊपरी सदन के लिए चुने गए थे, के 3 अगस्त 2017 को शपथ लेने के बाद यह स्थिति बनी है। यह पहली बार है जब मई 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद भाजपा राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है।

– बिज़नेस स्टैंडर्ड (4 अगस्त 2017)

भारत पांच साल में निरक्षरता को खत्म कर देगा

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर के मुताबिक भारत अगले पांच वर्षों में निरक्षरता को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा, "आजादी के बाद साक्षरता दर 18 प्रतिशत थी। आज यह 80 प्रतिशत तक बढ़ गई है और मैं गारंटी देता हूं कि अगले पांच सालों में यह 100 प्रतिशत हो जाएगी। देश में कोई निरक्षरता नहीं होगी।" उन्होंने युवाओं को शामिल करने की बात की और पढ़ाई पूरी न कर सकने वालों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को अधिक रोचक बनाने पर जोर दिया।

– द हिंदू (6 अगस्त)

गरीबों के लिए एलपीजी सब्सिडी बरकरार रहेगी

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी सिलेंडर पर गरीबों को मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी पर सब्सिडी को ख़त्म करने की हमारी कोई योजना नहीं है। गरीबों और आम लोगों के लिए एलपीजी और केरोसीन पर सब्सिडी जारी रहेगी। उत्तर-पूर्व में एलपीजी संकट से निपटने के लिए मंत्रालय ने बांग्लादेश के साथ चिट्टगोंग से त्रिपुरा तक प्राकृतिक गैस ले जाने के लिए एक पाइप लाइन बिछाने की बात की है। **– इकोनॉमिक टाइम्स (7 अगस्त)**

नोटबंदी के बाद आयकर रिटर्न भरने वालों में 25 प्रतिशत की बढ़त

नोटबंदी का सकारात्मक प्रभाव अब और अधिक स्पष्ट हो रहा है। आयकर विभाग के अनुसार साल 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 25 प्रतिशत बढ़कर 2.82 करोड़ हो गई है। विभाग ने कहा है, "नोटबंदी और ऑपरेशन क्लीन मनी के परिणामस्वरूप इस साल दाखिल की गई आयकर रिटर्न (आईटीआर) की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है।" आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में जमा बेहिसाब धन पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन क्लीन मनी चलाया था। **– द टाइम्स ऑफ इंडिया (7 अगस्त)**

स्पॉट विचार...

प्रगति स्वतंत्रता में निहित है। बिना स्वशासन के न औद्योगिक विकास संभव है, न ही राष्ट्र के लिए शैक्षिक योजनाओं की कोई उपयोगिता है। देश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न करना सामाजिक सुधारों से अधिक महत्वपूर्ण है।

- बाल गंगाधर तिलक

ये ज़रूरी है कि हम 'हमारी राष्ट्रीय पहचान' के बारे में सोचें जिसके बिना 'स्वतंत्रता' का कोई अर्थ नहीं है।

- पं. दीनदयाल उपाध्याय

भारत ने विदेशी कब्जे को हटाने के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी। स्वावलंबन की भावना देश भर में जाग्रत की। आजादी के बाद हमको अपना विकास अपने बलबूते पर करना चाहिए।

- कुशाभाऊ ठाकरे

आज वैश्विक निर्भरता का अर्थ यह है कि विकासशील देशों में आई आर्थिक आपदाएं विकसित देशों में संकट ला सकती हैं।

- अटल बिहारी वाजपेयी

प्रस्तुति: पंकज आनंद

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : .....

पूरा पता : .....

.....

..... पिन : .....

दूरभाष : ..... मोबाइल : (1)..... (2).....

ईमेल : .....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :..... दिनांक :..... बैंक : .....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

कमल संदेश

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

श्री वेंकैया नायडू के 13वें उपराष्ट्रपति बनने पर उनके नई दिल्ली स्थित निवास पर उन्हें बधाई देते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंन्द्र मोदी की कलाई पर राखी बांधती हुईं बालिकाएं

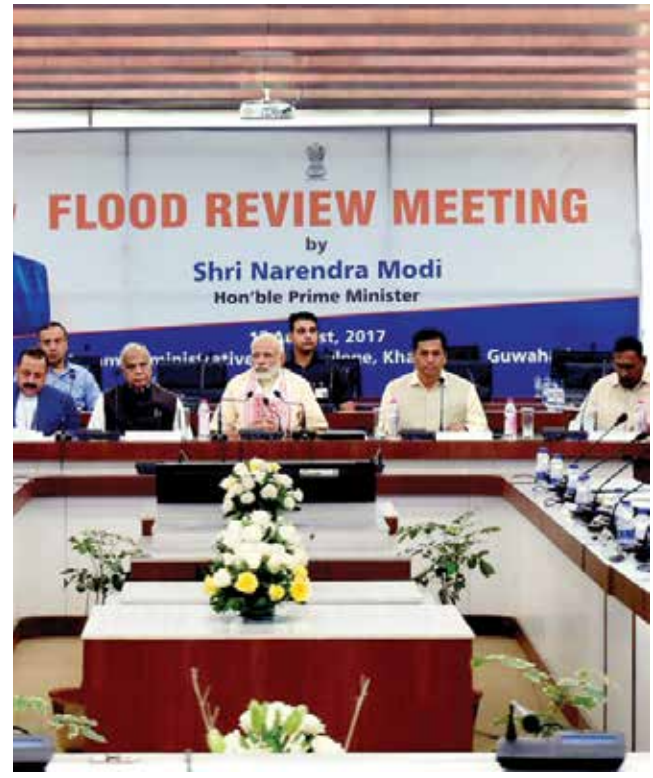

गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बने कमल संदेश के आजीवन सदस्य

कमल संदेश की कैशलेस सदस्यता लें!

आह्वान

आपको जानकर हर्ष होगा कि 6 दिसम्बर 2016 को पार्टी मुख्यालय में भाजपा 'कमल संदेश' का आजीवन सदस्य बनकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. **श्री अमित शाह** ने पत्रिका की सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि 'कमल संदेश' भारतीय जनता पार्टी की केन्द्रीय पत्रिका है और यह पाक्षिक रूप में हिन्दी–अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती है।

हमारे लिए यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 5000/– रुपए का चैक देकर 'कमल संदेश' की आजीवन सदस्यता ली। साथ ही केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर सहित अनेक केन्द्रीय एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों, माननीय सांसदों, विधायकों एवं पार्टी पदाधिकारियों द्वारा आजीवन सदस्यता ग्रहण की गई है।

'कमल संदेश' हिन्दी एवं अंग्रेजी के दोनों अंकों को 5000/– (पांच हजार रुपये) की सदस्यता शुल्क देकर नियमित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। अब 'कमल संदेश' के लिए कैशलेस भुगतान की भी सुविधा उपलब्ध है। कृपया 5000/– (पांच हजार) रुपये का योगदान कर आप भी 'कमल संदेश' (हिन्दी+अंग्रेजी) का आजीवन सदस्य बनें।

एक साल (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹350/-	**तीन साल** (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹1000/-
आजीवन (हिन्दी/अंग्रेजी)	—	₹3000/-	**आजीवन** (हिन्दी+अंग्रेजी)	—	₹5000/-

'कमल संदेश' के हमारे पाठकों से अनुरोध है कि इसकी सदस्यता लेकर जीवंत वैचारिक आंदोलन के भागीदार बनें।

कैशलेस बना 'कमल संदेश' सदस्य बनें और बनाएं

☞ **www.kamalsandesh.org, www.bjp.org** पर जाकर कैशलेस भुगतान क्रेडिट/डेबिट/नेटबैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं।

☞ साथ ही दिए बार कोड से मोबाइल द्वारा सीधा भुगतान भी कर सकते हैं।

chillr
ACCEPTED HERE
Scan the QR code to make a payment
Click on SCAN & PAY and enter amount
Add this contact to pay
+91 9911026172

"**कमल संदेश**" के नाम से कृपया चेक/ड्राफ्ट निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:
कमल संदेश, पीपी–66, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली– 110003